सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स

तीसरा सम्मेलन

संघर्षों की समीक्षा

एम० के० पंधे
सेक्रेटरी
सी० आई० टी० यू०

सन्मुखानन्द हाल
बम्बई, मई २१-२५, १९७५

सी आई टी यू के दूसरे सम्मेलन के बाद के दो वर्षों में मजदूर संघर्षों के उत्ताल तरंगों और मजदूर कतारों के बीच एकता के लिये बढ़ता आग्रह देखा गया इस छोटे समय में बहुत सारी बड़ी और लम्बी हड़तालें हुईं, पूंजीपतियों ने भी लम्बी तालाबन्दी और सामूहिक बर्खास्तगी के जरिये बदला लिया।

बेशक, हमारी यूनियनें इन संग्रामों की सबसे अगली कतार में उत्तरोत्तर आ रही हैं और सी आई टी यू की बढ़ती हुई भूमिका से अब मजदूर वाकिफ हैं। लेकिन, देश में हड़ताल की जो नई लहर आई है; हमारे नेतृत्व में किये गये संग्राम उसका सिर्फ एक हिस्सा ही है।

इनमें से कुछ यूनियनें किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन से सम्बद्ध नहीं हैं। मार्के की एक बात यह है कि पुलिस दमन और मालिकों के किराये के गुण्डों की गुण्डागर्दी के बावजूद इन संग्रामों का विराट हिस्सा एकजुट होकर लड़ा गया।

रेल हड़ताल

हमारे एरनाकुलम सम्मेलन के बाद सबसे महत्वपूर्ण संग्राम है रेल मजदूरों की देशव्यापी २० दिवसीय हड़ताल जिसके सामने इस काल के दूसरे तमाम संग्राम बौने बन गये। भारतीय रेल मजदूरों के इतिहास में इतनी शक्तिशाली औद्योगिक कार्रवाई इससे पहले कभी संगठित नहीं की जा सकी थी।

यह हड़ताल १७ लाख रेल मजदूरों में वर्षों से जमे असंतोष का ही नतीजा थी। ए आई आर एफ और एन एफ आई आर नेतृत्व द्वारा अपनायी गयी वर्ग सहयोगवादी नीति और प्रत्येक संग्राम के प्रति उनके विरोधी रुख ने दशकों

से कोई औद्योगिक कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन ए आई आर एफ के नेतृत्व में परिवर्तन और २७ फरवरी १९७४ को एक कंवेन्शन में ११० विभागीय संगठनों को एकजुट करने के लिये नये नेताओं की पहल ने पूरे देश के रेल मजदूरों में अभूतपूर्व जोश पैदा किया। रेल मजदूरों के संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन सी सी आर एस) का निर्माण किया गया जो रेल मजदूरों के संग्रामी मिजाज का प्रतीक थी। ८ मई १९७४ से हड़ताल शुरू करने के एन सी सी आर एस के आह्वान का रेल मजदूरों से पुरजोर स्वागत किया।

मजदूरों के तेवर को देखकर सरकार ने एक ओर बातचीत का दिखावा करके टालने का कौशल अपनाया तथा दूसरी ओर वह सभी प्रकार के दमन की तैयारी में जुट गई। समझौता वार्ता का प्रहसन शुरू करने के पहले ही सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की सूची तैयार करने और उन पर नजर रखने का एक गोपनीय सरकुलर जारी किया गया। इस तरह जबकि वार्त्ता चल रही थी, सरकार ने १ मई १९७४ को बड़े पैमाने पर नेताओं और सक्रिय मजदूर कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और सम्पूर्ण देश में इसके विरोध में स्वतः स्फूर्त प्रतिवाद हड़तालें संगठित की गईं। इस तरह मजदूरों के पास ८ मई को रेल का चक्का जाम करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था और हड़ताल शुरू हो गई।

रेल मजदूरों के खिलाफ सरकार ने वास्तव में युद्ध की घोषणा कर दी। पुलिस और गुण्डों ने रेल मजदूरों और उनके परिवारों पर बेइन्तहां आतंक का राज थोप दिया। डी आई आर, मीसा का बेहिचक इस्तेमाल किया गया। ५० हजार मजदूरों की गिरफ्तारी और उनके परिवार के सदस्यों पर अत्याचारों के बावजूद, दमन का मुकाबला करने मे रेल मजदूरों ने बेमिसाल दिलेरी का परिचय दिया। आल इण्डिया रेडियो के झूठे प्रचारों के बावजूद, हड़ताल ने सम्पूर्ण रेल व्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया।

पुलिस जुल्म और आतंक के खिलाफ तथा रेल मजदूरों के समर्थन में छः केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक दिन के भारत बन्द का आह्वान किया जिसका पालन अधिकांश राज्यों में किया गया।

यह अपने तरह की सर्व प्रथम कार्रवाई थी जिसने अन्य क्षेत्र के मजदूरों के प्रति एकजुटता संग्राम में मजदूरों और वेतनभोगी कर्मचारियों की चेतना की ऊँचाई का इजहार किया। अनेक राज्यों में यह एकजुटता संघर्ष बहुत ही व्यापक था और जिन्हें कभी भी इस संग्राम में नहीं खींचा गया था, वे तबके भी इस बार भारी संख्या में इसमें शामिल हुए। इस हड़ताल ने, हड़ताली रेल

मजदूरों के मनोबल को ऊंचा उठाने में एक अहम भूमिका अदा की।

हालांकि हड़ताल के दौरान शानदार एकता हासिल की गई थी, लेकिन खुद संग्राम में ही कमजोरियां थीं। पहली, इतने विराट संग्राम के संचालन के लिये पर्याप्त तैयारी नहीं थी। कुछ लीडरों ने तो यहां तक सोचा कि हड़ताल की धमकी देने मात्र से ही सरकार से कुछ सुविधायें मिल जायेंगी जिसके बल पर वे हड़ताल वापस ले लेंगे।

दूसरी, हड़तालो मजदूरों और उनके परिवारों पर सरकारी दमनयंत्रों के टूट पड़ने के बारे में रेल आन्दोलन के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को नहीं बताया गया तथा इन दमनात्मक कदमों का सामना करने के लिये सांगठनिक तैयारी नहीं की गई।

तीसरी पुलिस के हमलों का सामना करने के लिये यदि कारगार तैयारी पहले से की गई होती तो मजदूर और भी अच्छा करते। तीसरी, रेल आन्दोलन में ए आई टी यू सी और दूसरे नेतृत्व के विश्वासघातक रवैये ने मजदूरों को पस्त-हिम्मत करने के लिये सब कुछ किया।

चौथी, इतनी विराट हड़ताल चलाने के लिये मजदूरों की कतारों से एक शक्तिशाली पहल का निर्माण करने में रेल आन्दोलन असफल रहा। इसी के चलते लम्बी हड़ताल चलाने की स्थानीय पहल का भी अभाव देखा गया।

एन सी सी आर एस में ए आई टी यू सी के लीडरों ने बेशर्मी के साथ १५ मई के बाद हड़ताल वापस लेने का प्रस्ताव रखा। २६ मई को ए आई टी यू सी के लीडरों ने मजदूरों का आह्वान करते हुए अखबारों में खुलेआम यह बयान दिया कि वे आंचलिक और विभागीय तौर पर हड़ताल खत्म कर दें। इस उलझनपूर्ण स्थिति में, २७ मई को जेल में बन्द एन सी सी आर एस के सदस्यों की ओर से यह प्रस्ताव आया कि एकतरफा तौर पर हड़ताल खत्म कर दी जाय।

ए आई टी यू सी नेतृत्व की वर्ग सहयोगवादी नीति और इंदिरा गांधी की सरकार का दबाव उनको घृणित आत्मसमर्पण और रेल मजदूरों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाने के रास्ते पर ले गया।

सी आई टी यू के प्रतिनिधि का० समर मुखर्जी और ए आई आर एफ के महासचिव का० प्रिय गुप्त ने एन सी सी आर एस की बैठक में एकतरफा हड़ताल खत्म करने का विरोध किया। हड़ताल के इस तरह खत्म किये जाने से मजदूरों को सदमा पहुंचा और बहुत जगहों में मजदूरों ने तुरत ड्यूटी शुरू

नहीं की।

हड़ताल वापस लेने के बाद सरकार और भी बदला लेने पर उतारू हो गई, यद्यपि पहले उसने नरमी बरतने का वादा किया था और हड़ताल उठा लिये जाने पर बातचीत करने को सहमत हुई थी। नीचे के स्तर पर हर अफसर ने बर्खास्त मजदूरों से दया की भीख मांगने और मुचलका देने का आदेश दिया, लेकिन मजदूरों के विराट बहुमत ने इन अपमानजनक शर्तों को ठुकरा दिया। एन सी सी आर एस से समझौता करने से सरकार ने फिर इनकार किया और एन सी सी आर एस के मतभेदों से फायदा उठाने की कोशिश की। १९७५ की जनवरी की समाप्ति तक २० हजार रेल मजदूर बर्खास्तगी की हालत में रह रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में, एन सी सी आर एस का काम काज चलाना बेहद कठिन हो गया और नेतृत्व के एक हिस्से द्वारा इसे खत्म कर देने की कोशिश की गई। सिर्फ रेलवे बोर्ड के नौकरशाहों ने बर्खास्तगी को अधिक समय तक जारी रखने और आन्दोलनों में फूट डालने में इस मौके का इस्तेमाल किया।

इतना होने पर भी रेल मजदूरों को हराने में सरकार नाकाम रही। ये मजदूर पिछले २० वर्षों के संग्राम की अपेक्षा २० दिनों की अपनी हड़ताल में कांग्रेस सरकार के असली चरित्र को ज्यादा अच्छी तरह समझ गये।

रेल हड़ताल का असर इतना व्यापक था कि इसे विदेशों के विभिन्न संगठनों से भी एकजुटता और सहयोग प्राप्त हुआ। जापान के सबसे शक्तिशाली ट्रेड-यूनियन संगठन सोहयो ने न सिर्फ प्रस्ताव पास कर समर्थन किया बल्कि उसने इस रेल हड़ताल को ५ लाख रुपये चन्दा दिये। १० हजार डालर का एक दूसरा चेक जापान की रेलवे यूनियन द्वारा भेजा गया। मगर यह दोनों चन्दा भारत सरकार द्वारा रोक लिया गया। भारत में रेल मजदूरों की हालत देखने के लिये इंटरनेशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ने एक अध्ययन दल भेजने की इच्छा जाहिर की तो भारत सहकार ने उस प्रतिनिधिमण्डल को वीसा देने से इनकार कर दिया।

इसे नोट करना चाहिये कि रेल मजदूरों के आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये रास्ते का निर्माण करने में लोको रनिंग मजदूरों की दो-दो हड़तालों ने बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के नेतृत्व में हुए अगस्त १९७३ की लोको मजदूरों की हड़ताल ने रेलवे के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के पेशेवर हड़ताल तोड़कों पर

बड़ा भारी आघात किया। चालू १४ घंटे की ड्यूटी की जगह ८ घण्टे की ड्यूटी लागू करना करना ही हड़ताली मजदूरों की मुख्य मांग थी। अपनी यूनियनों को मान्यता देने की मांग भी उन्होंने की।

हड़ताल मुकम्मिल हुई तथा इसने रेल व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। आखिरकार सरकार और रेल बोर्ड के नौकरशाहों को झक मार कर मजदूरों की मांगें माननी पड़ीं। पहले दौर में, काम के घण्टे को घटाकर १४ की जगह १० करने पर सरकार राजी हो गई। अर्थात् मजदूरों की एक बड़ी भारी जीत हुई। बर्खास्तगी के तमाम आदेशों को वापस लेने तथा डी आर आई आर में गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने पर भी वह राजी हो गई। सरकार ने स्वीकार किया कि बाकी माँगों पर फैसले के लिये ए आई एल आर एस ए के प्रतिनिधियों के साथ वह बातचीत शुरू करेगी। इससे पहले उन्होंने लोको रनिंग मजदूरों का बेरहम दमन किया, लेकिन हड़ताल के दौरान हासिल मजदूरों की उल्लेखनीय एकता के कारण सामयिक तौर पर नौकरशाहों को पीछे हटना पड़ा था। आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ के साथ रेलवे बोर्ड ने जो समझौता किया वह लोको रनिंग मजदूरों के सामूहिक दबाव का ही फल था तथा यह पहला मौका था कि सरकार यह मानने पर मजबूर हुई थी कि मान्यता प्राप्त दो फेडरेशनों के अलावा बाहर भी प्रतिनिधि यूनियनें हैं। इन दो यूनिययों ने ८ घण्टा काम के आधार पर समझौते का विरोध किया, यद्यपि जमाना गुजर गया है उनको मान्यता प्राप्त किये, मगर वे मांग नहीं हासिल कर सके।

हड़ताल की सफलता ने लोको मजदूरों की कतारों और दूसरे विभागों के रेल मजदूरों में आत्म विश्वास पैदा किया। अपनी विभागीय मांगों को हासिल करने के लिये वे संग्राम की बात करने लगे। लेकिन समझौते की रोशनाई सूखने के पहले ही, रेलवे बोर्ड के अफसरों ने एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये अड़ंगेबाजी की खोज शुरू कर दी कि व्यवहार में समझौते को लागू करना असम्भव हो जाय।

लिहाजा २६ नवम्बर १९७३ को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने के जरिये लोको रनिंग मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दी। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान न दिया। इस तरह १५ दिसम्बर १९७३ से हड़ताल पर जाने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। यह पहले हड़ताल से भी ज्यादा व्यापक थी। पहले की हड़ताल से शिक्षा लेने के बजाय अधिकारियों ने डी आई आर मीसा आदि के अन्तर्गत बेहिचक गिरफ्तारी, टैरिटोरियल फौज, अवकाश प्राप्त

लोकोमैन, डीजल के ड्राइवरों आदि का सहारा लिया, पर रेल का चक्का टस से मस नहीं हुआ। आखिर उन्हें फिर एक बार झुकना पड़ा और २४ दिसम्बर के समझौते पर अमल करना स्वीकार किया। जब समझौते को अस्वीकार करने की कोशिश की गई तो, धर-पकड़ के बावजूद उत्तर पूर्व सीमा त रेलवे के मजदूरों ने १० घण्टे अधिक काम करने से इनकार किया, आन्दोलन बढ़ता ही गया।

मजदूरों के एकजुट संग्राम को दबाने में असफल होकर रेलवे बोर्ड ने दरार पैदा करने की चाल अपनायी। और ए आई टी यू सी ने रेलवे बोर्ड को उसके इस नापाक काम में पूरी सहायता की। लेकिन लोको मजदूरों में एकता की प्रबल इच्छा ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया।

लोको मजदूरों की दोनों हड़तालों और अखिल भारत रेल हड़ताल के दौरान, सी आई टी यू ने रेल मजदूरों के प्रति पूर्ण एकजुटता जाहिर की। बर्खास्त रेल मजदूरों को सी आई टी यू ने जो कानूनी मदद दी, उसका ब्योरा अलग से एक नोट में दिया जाता है। इन संग्रामों में रेल मजदूरों और अन्य संगठित मजदूरों के बीच विभाजन की खाई को पाट दिया गया। रेल मजदूरों के बीच अपने काम को और भी ज्यादा ध्यान देकर करने में सी आई टी यू को इस मौके का फायदा उठाना होगा, ताकि रेल मजदूरों को एकजुट संग्रामों का और अच्छी तरह समन्वय और मार्ग दर्शन किया जा सके।

ए आई टी यू सी का नेतृत्व चुपचाप सरकार से बात चला रहा है और रेलवे बोर्ड चोरी चुपके उनके द्वारा गठित नये फेडरेशन को मान्यता दे रहा है।

रेल आन्दोलन के अन्दर की फूटपरस्त ताकतें रेलवे बोर्ड के इशारे पर एन सी सी आर एस में और उससे सम्बन्धित उच्च संगठनों जैसे लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। अत: एन सी सी आर एस की रक्षा और उसे शक्तिशाली बनाने के प्रयास करने होंगे। रेल मजदूरों के अखिल भारत कनफेडरेशन और एन सी सी आर एस के बीच एकता स्थापित करने की कोशिशें करनी होंगी। यह कनफेडरेशन के नेतृत्व की एक कमजोरी है कि अन्य क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गयी मूल्यवान सहायता पर वे विचार नहीं करते। यह महत्वपूर्ण है कि वे रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रचार के शिकार हुए हैं कि रेल आन्दोलन में तोड़फोड़ बाहरी शक्तियां कर रही हैं। केवल धैर्यपूर्वक समझा बूझा कर और पीछे लग कर ही हम रेल आन्दोलन के तमाम हिस्सों की एकता कायम कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इस

कार्य के लिए सी आई टी यू को खास ध्यान देना होगा।

राज्य सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष

४० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतक वेतन और शत प्रतिशत मंहगाई भत्ते की अपनी मांगों के लिये एकजुट संग्राम करते रहे हैं। यद्यपि उन्होंने प्रदर्शनों और सभाओं के माध्यम से बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सरकार ने इस मामले को निबटाने से इनकार किया। राज्यव्यापी हड़तालें भी की गईं, लेकिन मांगों का फैसला नहीं हुआ। इससे भारतव्यापी संयुक्त कार्रवाई का विचार उठा और अखिल भारत राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन ने ९ अप्रैल १९७४ को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया। बुनियादी और सामान्य मांगों के लिये इस क्षेत्र के कर्मचारियों की यह पहली हड़ताल थी। हड़ताल के दौरान, सरकार ने तलब काटने, नौकरी की धारावाहिकता खत्म करने, पेन्शन और ग्रेच्यूटी जब्त करने तथा अन्य सजाएं देने की धमकी दी। २००० कर्मचारियों को गिरफ्तार कर और हजारों को झूठे मामलों में फंसाकर केरल की अच्युत मेनन सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को पीछे छोड़ दिया। फिर भी हड़ताल पूरी सफल रही। तमाम राज्यों में काम काज ठप हो गया। अकेले महाराष्ट्र सरकार ने एक लाख कर्मचारियों की नौकरी की धारावाहिकता भंग की। इसे ही अन्य राज्यों में भी दोहराया गया; लेकिन राज्य कर्मचारियों ने बड़े असरदार तरीके से इन कदमों के खिलाफ संग्राम किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, प० बंगाल, बिहार आसाम तथा अन्य सूबों के राज्य कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्यवाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कर्मचारी डरे नहीं और उन्होंने अपना संग्राम जारी रखा। राज्य सरकारी कर्मचारियों के हाल का संग्राम ही उनके जुझारू प्रतिरोध का उज्जवल उदाहरण है जिससे खुद राज्य सरकार भी हिल उठी। फरवरी १९७५ में केरल में राज्य सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी लगातार हड़ताल के मध्य कर्मचारियों ने एकता की एक नयी चेतना दिखाई। अन्य क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ एकजुटता संग्राम में भी राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाधिक योगदान करते रहे हैं।

हड़तालों की नयी लहर

१९७४ के प्रारम्भ में, देश में तीन बड़ी हड़तालों की बाढ़ आयी, जिनमें लाखों मजदूर शामिल हुए। ये थीं महाराष्ट्र के दो लाख सूती मिल मजदूरों की हड़ताल, तमिलनाडु के डेढ़ लाख सूती मिल मजदूरों की हड़ताल और प० बंगाल आंध्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आसाम में ३ लाख चटकल मजदूरों की हड़ताल।

चटकल मजदूरों की ३३ दिवसीय हड़ताल पहली देशव्यापी उद्योगवार हड़ताल थी। चटकल मजदूरों के आम मांग पत्र पर यह हड़ताल हुई। उनकी मांगे थीं : सभी स्तर के मजदूरों के लिये ग्रेड और स्केल तय करो, बगैर हर्जाना दिये जूट मिलों और विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करो, कच्चे पाट की कीमत ८० रु० प्रतिमन तय करो, २० प्रतिशत बोनस तथा बदली मजदूरों को राहत दो। यद्यपि हड़ताल की नोटिश सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई थी, लेकिन ठीक हड़ताल शुरू होने के वक्त, १३ जनवरी १९७४ की आधीरात को आई एन टी यू सी, एच एम एस के एक हिस्से और एन एफ आई टी यू ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मगर सी आई टी यू, ए आई टी यू सी यू टी सी (लेनिन शरणी) और एच एम एस का एक हिस्सा अपने फैसले पर डटे रहे और मुकम्मिल हड़ताल हुई। आई एन टी यू सी के अनुगामी मजदूर भी अपने नेतृत्व को ठुकरा कर हड़ताल में शामिल हुए। इससे पूर्व, ५ नवम्बर १९७३ को मांगों के लिये प० बंगाल में एक जुट होकर एक दिन की हड़ताल की गयी थी। ३१ जनवरी १९७४ को प० बंगाल में चटकल मजदूरों के समर्थन में सफल औद्योगिक आम हड़ताल हुई।

प० बंगाल सरकार ने जूटशाहों का खुलेआम पक्ष लिया। मगर फिर भी आइ एन टी यू सी व दूसरों के साथ हुये समझौते के साथ एक एक्सग्राशिया रकम देने को उन्हें कहना पड़ा। छः ट्रेड यूनियनों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया. मगर अतिरिक्त सुविधाओं के मिलने से आइ एन टी यू सी की हार को देखते हुये १५ फरवरी को हड़ताल वापस ले ली गई। जीत और जरूरत पड़ने पर हराने के उत्साह के साथ मजदूर काम पर गये।

३० दिसम्बर को बम्बई के सूतीमिल मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई और ए आई टी यू सी, सी आई टी यू तथा लाल निशान यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से लड़ी गई, यद्यपि आइ एन टी यू सी ने २५.०० रु० की बढ़ोत्तरी स्वीकारते

हुये एक विश्वासघाती समझौता कर लिया था जब कि मजदूरों की मांग ४२५ रु० न्यूनतम तलब तय करने की थी। सात दिन के हफ्ते का भी यूनियनों ने विरोध किया और वार्षिक बढ़ोत्तरी, शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति, सूचकांक की जालसाजी समाप्त करने, और अधिक बोनस की मांग की। आई एन टी यू सी के विश्वासघात के खिलाफ मजदूरों की स्पष्ट राय के बावजूद सरकार आइ एन टी यू सी का ही पक्ष लेने लगी और मजदूरों पर हमले के लिये शिवसेना के गुण्डों को भड़काया। हरिजन युवकों के जुझारू हिस्से दलित पैंथर को हमले का खास निशाना बनाया गया। जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो नाईक सरकार की पुलिस उन पर टूट पड़ी और गोली चलाकर एक मजदूर की हत्या कर दी।

जब दमन से हड़ताल न टूटी, तो सरकार की खिदमत में डांगे हाजिर हुये। मिल मालिकों और डांगे के बीच एक गोपनीय समझौता हुआ जिसके अनुसार मजदूरों को ४ रु० की बढ़ोत्तरी दी जाती। डांगे ने एकतरफा तौर पर हड़ताल खत्म कर दी, उन यूनियनों से सलाह मशविरा किये बगैर जो संयुक्त रूप से हड़ताल चला रही थीं। सरकारी मजदूरों को आधी सुविधाएँ ही दी गईं और कुछ मिलों में तो उनके विश्वासघात के बाद भी ज्यादा दिनों तक हड़ताल जारी रही।

१ फरवरी १९७४ से सी आई टी यू, ए आई टी यू सी और एच एम एस को लेकर बनी संघर्ष समिति के नेतृत्व में तमिलनाडु की १८० मिलों के एक लाख से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल की। एक ही प्रकार की दस सूत्री मांगों के लिये यह हड़ताल हुई। आई एन टी यू सी इसमें ११ दिनों के बाद शामिल हुई।

लेकिन शुरू से ही ए आई टी यू सी और एच एम एस के नेताओं में ढुलमुलपन देखा गया और गुप्त रूप से वे सरकार के साथ समझौता वार्त्ता चलाते रहे। जब तमिलनाडु के श्रममन्त्री के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिये उन्होंने संघर्ष समिति से सी आई टी यू को निकालने की साजिश की, तो सी आई टी यू को अकेले ही हड़ताल जारी रखनी पड़ी। इस गद्दारी को मजदूर समझ गये और ५ मार्च तक हड़ताल पर डटे रहे, जब तक कि मालिक और ज्यादा सुविधायें देकर समझौता करने पर राजी न हुये।

गोदी हड़ताल

१०० रु० अन्तरिम राहत, मूल वेतन के साथ मँहगाई भत्ते को मिला देने की मांग पर तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किये बगैर वेतन कमेटी की नियुक्ति का विरोध करते हुए समूचे देश के गोदी मजदूर १६ जनवरी १९७५ से हड़ताल पर चले गये। इस हड़ताल का आह्वान तमाम यूनियनों ने किया और यह पूरी तरह सफल रही। हड़ताल तोड़ने के लिये सरकार ने डी आई आर के तहत इस पर रोक लगा दी।

ऐसी स्थिति में, बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रजनी पटेल और आई एन टी यू सी के महासचिव श्री जी रामानुजम ने हस्तक्षेप किया और आई एन टी यू सी तथा एच एम एस के फेडरेशनों से हड़ताल के पूर्व के सरकारी शर्तों को मानकर हड़ताल वापस लेने के लिये उन पर दबाव डाला। दिल्ली में जल्दीबाजी में बुलाई गई बैठक के परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ। जिसके अनुसार अतिरिक्त मँहगाई भत्ते के तौर पर ५० रु० मिला जिसका आधा जाम कर दिया जायेगा और १९७४ के बकाये के रूप में ३०० रु० मिला। वास्तव में नेतृत्व ने सरकार द्वारा गठित उस वेतन कमेटी को ही स्वीकार लिया जिसका उन्होंने पहले बहिष्कार किया था! बाद में इस आत्म समर्पण पर ए आई टी यू सी के लीडरों ने भी हस्ताक्षर किया। आई एन टी यू सी, एच एम एस तथा ए आई टी यू सी फेडरेशनों के नेतृत्व में गोदी मजदूरों की उन तमाम समस्याओं को, जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ, जहाजरानी मंत्रालय की दया पर छोड़ दिया। हड़ताल खत्म करने के पहले मजदूरों की राय जानने के जनवादी नियमों को भी इन तीन फेडरेशनों के नेताओं ने जान-बूझ कर ताक पर रख दिया।

हड़ताल के दौरान उल्लेखनीय एकता कायम हुई थी, लेकिन नेतृत्व के आत्म-समर्पण के चलते सभी मांगे नहीं हासिल की जा सकीं। बहुत सारी मांगों पर फैसला न होने के कारण मजदूरों का असंतोष तेजी से बढ़ेगा और इसमें शक नहीं कि आने वाले दिनों में गोदी मजदूरों के संग्राम का एक और दौर आयेगा।

जीवन बीमा कर्मचारियों की सफल हड़ताल

आल इण्डिया इंस्योरेंस इम्प्लाइज एसोसियेशन (ए आई आई इ ए) के नेतृत्व

में ४० हजार बीमा कर्मचारियों का संग्राम इस काल में सबसे डटकर किये गये संग्रामों में एक है। प्रबन्धक जान-बूझकर मांग पत्र पर समझौता वार्ता टाल रहे थे और दूसरी ओर उन्होंने विरोध प्रदर्शित किये जाने के कारण १००० अगुआ कार्यकर्त्ताओं को या तो मुअत्तल कर दिया या चार्जशीट दी। प्रतिशोध की इस नीति के खिलाफ ए आई आई ई ए ने २८ दिसम्बर १९७३ से बेमुद्दत हड़ताल की घोषणा की। प्रबन्धकों ने ६ डिवीजनों में तालाबन्दी की घोषणा की जिसका जवाब इन डिवीजनों के कर्मचारियों ने हड़ताल से दिया।

आई एन टी यू सी और ए आई टी यू सी के नेताओं ने संग्राम में तोड़-फोड़ करने में एड़ी–चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जीवन बीमा कर्मचारियों की एकता का हम अभिनन्दन करते हैं। आखिर में जनवरी '७४ में एल आई सी के अधिकारी समझौता करने पर मजबूर हुये। समझौते के अनुसार मजदूरों की तलब में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें बोनस शामिल नहीं है।

वाध्य होकर अधिकारियों को बर्खास्तगी के तमाम आदेश वापस लेने पड़े। इस तरह इस संग्राम के कारण जीवन बीमा कर्मचारियों की एकता और भी मजबूत हुई और आन्दोलन में फूटपरस्त ताकतें विछिन्न हुई।

हवाई जहाज के कर्मचारियों का संग्राम

काम का अतिरिक्त बोझ लादते हुये नयी पारी प्रथा चालू करने के खिलाफ इण्डियन एयर लाइंस के कर्मचारियों का संग्राम बड़ा ही विस्तृत था। इस नयी पारी के सम्बन्ध में एयर कारपोरेशन इम्पलाइज यूनियन से परमार्श भी नहीं किया गया। कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन १२ नवम्बर १९७३ से आरम्भ किया और फैसला लिया कि यदि नयी पारी प्रथा वापस नहीं ली जाती है तो २५ नवम्बर से वे हड़ताल करेंगे। कुख्यात एयर मार्शल पी सी लाल (अवकाश प्राप्त) की मुखियागिरी में इण्डियन एयर लाइन्स के अधिकारियों ने २४ नवम्बर से तालाबन्दी की घोषणा कर दी और अपमानजनक शर्त्तों को मान लेने वाले व्यक्तियों के लिये तालाबन्दी उठा लेने का कदम उठाया। उनका यह कदम आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व था। प्रारम्भ में अपने कुछ नेताओं की गद्दारी के बावजूद एयर लाइन्स कर्मचारियों ने डट कर मोर्चा लिया। अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित समझौते के मसौदे का उद्देश्य था कर्मचारियों के तमाम

ट्रेड यूनियन अधिकारों का दमन और ऐयर लाइन्स के संचालन में सैनिक नियमों को चालू करना। फालतू "खर्च पर" काबू पाने के बहाने कर्मचारियों को मिल रही सुविधायें रोक दी गईं। आखिर में, एयर लाइन्स कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन की कमजोरियों से फायदा उठाने में अधिकारी सफल हो गये और कर्मचारियों पर मनमाना शर्त थोप दी गयी। सी आई टी यू ने एयर लाइंस के कर्मचारियों के संग्राम का समर्थन किया और तमाम क्रूर तरीकों की निन्दा की। नियमत: तालाबन्दी अभी भी नहीं खत्म की गई है और हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक संधि को मानने के लिये यूनियन को मजबूर किया गया है।

इसी तरीके से एयर इंडिया के अधिकारियों ने पायलटों पर स्लिप-प्रथा थोप दिया जिससे नवम्बर १९७४ में ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं बन्द हो गईं। पायलटों को झुकाने के लिये यहां भी निर्मम तरीके अपनाये गये। अधिकारियों के अत्याचार के सामने पायलटों को अपना संग्राम वापस लेना पड़ा। इस संग्राम के दौरान भी तालाबन्दी की गई और सिर्फ उनके लिए इसे उठाया गया जिन्होंने 'स्लिप प्रथा" मंजूर की।

इन दो संग्रामों में यह देखा गया कि कर्मचारियों की मांगों के साथ निरंकुश रवैया अपनाया जा रहा है। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये खतरा है। यदि ट्रेड यूनियन आन्दोलन की अग्रगति जारी रखनी है तो इस खतरे के खिलाफ ऐक्यवद्ध होकर संग्राम करना होगा। यह भी नोट करना चाहिये कि हवाई जहाज के कर्मचारियों के संग्राम का दमन इसलिये किया जा रहा है क्योंकि उनकी यूनियनें विभागों पर आधारित हैं और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच एकजुटता संग्राम का सर्वथा अभाव है। और तो और, जब इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों पर हमले हो रहे थे, तब कुछ एयर इण्डिया के कर्मचारी इंडियन एयर लाइन्स के जहाजों पर काम कर रहे थे। इस तरह इण्डियन एयर लाइन्स कर्मचारियों के प्रति एयर इंडिया के कर्मचारियों की एकजुटता का सर्वथा अभाव था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संग्राम

तीसरे पे-कमीशन की सिफारिशों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बेहद गुस्सा हुये। स्थानीय और आंचलिक तौर पर विभिन्न कंवेन्शनों और प्रदर्शनों के जरिये कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। सरकार ने जो मामूली

सुधार किये, कर्मचारी उससे सन्तुष्ट नहीं हुये और उनका आन्दोलन सब तरफ फैलता रहा। तीसरे पे कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ और सबके लिये बोनस की मांग पर जुलाई १९७३ में यू सी टी यू के आह्वान पर एक कंवेन्शन हुआ जिसे शानदार समर्थन मिला। इससे एकजुट संग्राम के लिये मजदूरों की प्रबल इच्छा जाहिर हुई।

ए आई टी यू सी नेतृत्व ने एकजुट संग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया और कुछ सुविधायें प्राप्त करने के लिये कांग्रेस सरकार से सांठ-गांठ की कोशिश की। सक्रिय रूप से उन्होंने आन्दोलन को तोड़ा और सरकार को अपना घातक खेल खेलने में मदद की।

एन सी सी आर एस के गठन और रेलवे बोर्ड के साथ समझौता वार्त्ता असफल होने पर लगातार हड़ताल चलाने के उसके फैसले के बाद, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन में एक नया जोश आया। १५ मार्च १९७४ को नयी दिल्ली में ए आई आर एफ के आह्वान पर एक राष्ट्रीय कंवेन्शन हुआ, जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आन्दोलन में काम करने वाले तमाम ग्रूपों ने भाग लिया।

कन्वेन्शन में तय पाया कि रेल मजदूरों द्वारा हड़ताल का फैसला लिये जाने पर, देशव्यापी जन कार्रवाई की तैयारी की जाय। सी आई टी यू की ओर से कन्वेन्शन में भाषण देते हुए का० बी० टी० रणदिवे ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिये सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी संग्राम करें, सी आई टी यू उनका दृढ़ समर्थन करता है।

कन्वेन्शन के फैसले के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और मजदूर यूनियनों के कनफेडरेशन ने ८ और ९ मई को "बैठे रहो" और १० मई से आम हड़ताल का आह्वान किया। लेकिन सरकारी कर्मचारी आन्दोलन का एक हिस्सा श्री मधुसूदन और ओ० पी० गुप्ता के नेतृत्व में अपने वादे से मुकर गया और औद्योगिक कार्रवाई के आहवान कर विरोध किया। इससे केन्द्रीय कर्मचारियों के आन्दोलन में व्यापक दरार पड़ी। दो दिनों के बाद ही हड़ताल वापस लेनी पड़ी जिससे कर्मचारियों में सामयिक पस्तहिम्मती छा गई।

केन्दीय सरकारी कर्मचारियों की कतारों को, खासकर डाक-तार कर्मचारियों को गोलबन्द करने का प्रयास कनफेडरेशन ने किया। कुछ महीनों तक बातचीत चलती रही और एकता की सम्भावना उज्जवल होने लगी। लेकिन जनवरी महीने में सरकार ने मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में अपना फैसला सुनाया

जिसके अनुसार, मंहगाई भत्ते की सिर्फ ३ किस्त देने की घोषणा की गयी, जबा कि उस वक्त पांच किश्तें बकाया थीं। घोषित इन तीनों किश्तों को भी या तो जाम कर दिया जायगा या कर्मचारियों के प्राविडंडफण्ड में जमा कर दिया जायेगा। मंहगाई भत्ते का बकाया ९८ करोड़ रुपया था, लेकिन कर्मचारियों को सिर्फ १२ करोड़ ही मिलता। मधुसूदन, ओ० पी गुप्त गुट ने सरकारी प्रस्ताव के आगे घुटने टेक दिये और वेतन तथा मंहगाई भत्ता जाम को स्वाकार लिया। इससे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में गुस्से की लहर दौड़ गयी। इन परिस्थिियों में एकता की बात निरर्थक साबित हो जाती।

जबकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एकता कायम करने की कोशिशों की पूर्ण सफलता की कामना हम करते हैं, तो यह केन्द्रीय कर्मचारियों के अधिकारों के लिये संघर्ष की बुनियाद पर होनी चाहिये, अधिकारों के समर्पण के जरिये नहीं।

वेतन जाम के खिलाफ अभियान

६ अप्रैल १९७४ के राष्ट्रपति का अध्यादेश और बाद में संसद द्वारा इसकी जगह बनाये गये कानून, जिसके अंतर्गत समुचे वेतन बृद्धि और आधे मंहगाई भत्ते को जाम कर दिया गया मजदूरों और कर्मचारियों के जीवनमान और तलब पर सबसे भयंकर हमला था। स्वाभाविक तौर पर ही, मजदूरों के सभी हिस्सों और आई एन टी यू सी को छोड़कर तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से इसके खिलाफ देशव्यापी आक्रोश पूर्ण प्रतिवाद किये गये। देश के सभी कोनों में विभिन्न रूप में स्वत: स्फूर्त विस्फोट हुए। वेतन जाम के खिलाफ संग्राम में पहला खून भरतपुर (राजस्थान) में बहा जहां बिड़ला के सिमको बैगन कारखाने के सी आई टी यू के तीन मजदूरों की हत्या की गई। यह हत्या उस वक्त की गई जब मजदूर वेतन जाम का प्रतिरोध कर रहे थे।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने वेतन जाम के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का फैसला लिया। २०-२१ जुलाई १९७४ की दिल्ली बैठक से यह फैसला लिया गया। उन्होंने ९ से १५ अगस्त तक वेतन जाम विरोधी सप्ताह मनाने का आहवान किया तथा मजदूरों से प्रत्येक कल-कारखाना, आफिस और अन्य संस्थान के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिये कहा गया।

इसी रास्ते पर चलते हुये २८ अगस्त को दिल्ली में वेतन जाम के खिलाफ मेहनतकशों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन हुआ। ए आई टी यू सी और आई एन टी यू सी को छोड़कर तमाम यूनियनों और विभिन्न फेडरेशनों के १४०० प्रतिनिधि इस कन्वेन्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सरकार के वेतन जाम के हमले को पराजित करने और प्रतिरोध करने के लिये मजदूर वर्ग में एकता के नये आग्रह का यह एक अनोखा प्रदर्शन था। उसने मजदूरों से एक सुस्थिर संग्राम चलाने के लिये भरसक व्यापक एकता कायम करने का आहवान किया।

फैसला लिया गया कि संग्राम के पहले दौर में ट्रेड यूनियनों को एकजुट आँचलिक, स्थानीय और राज्य स्तरीय कन्वेन्शन करने होंगे, विभिन्न स्तरों पर हड़तालें और प्रदर्शन संगठित करने होंगे।

राष्ट्रीय कन्वेन्शन के बाद पूरे देश में २०० आंचलिक, स्थानीय, और राज्य स्तरीय कन्वेन्शन किये गये। इन कन्वेन्शनों के माध्यम से वेतन जाम से उत्पन्न खतरे के प्रति मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों को जागृत करने में बड़ी भारी मदद मिली है। इन कन्वेन्शनों ने आगामी दिनों के विकट और लम्बे संग्राम के लिये एकता हासिल करने की जरूरत के प्रति भी मजदूरों को सचेत न करने में बेहद सहायता की। यहां तक कि वे मजदूर वर्ग के सबसे पिछड़े हिस्से को भी इस संयुक्त मंच में खींच लाये, जो पहले कभी न देखा गया।

सी आई टी यू के अलावा, जीवन बीमा, केन्द्रीय और राज्य सरकार, रेल, बैंक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के अन्य बहुत सारे संगठनों ने भी इन कन्वेन्शनों में सक्रिय दिलचस्पी दिखाई। यद्यपि ए आई टी यू सी में राष्ट्रीय कन्वेन्शन में भाग नहीं लिया, फिर भी राज्य स्तर के साथ ही कुछ स्थानीय कन्वेन्शनों में उसकी यूमिटें शामिल हुईं।

वेतन जाम के खिलाफ राज्यव्यापी बन्द आयोजित करने में केरल ने पहल की। यह बन्द १८ सितम्बर १९७४ को हुआ। आई एन टी यू सी को छोड़ कर तमाम यूनियनें इस बन्द में शामिल हुई। बन्द कामयाब रहा। यहां तक कि आकाशवाणी भी ठप्प हो गई।

दूसरी बन्द महाराष्ट्र में हुआ। आई एन टी यू सी को छोड़कर तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई कमेटी के आह्वान पर ३० अक्टूबर १९७४ को यह हड़ताल हुई। इसी दिन शाम को ४०,००० मजदूरों का विराट जुलूस निकला जो अन्त में एक रैली में बदल गया। इस रैली के वक्ताओं में सी आई टी यू के अध्यक्ष का० बी० टी० रणदिवे भी थे।

वेतन जाम और सरकार की अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ २१ नवम्बर १९७४ को राजस्थान में राज्यव्यापी बन्द का पालन किया गया। बन्द का आह्वान सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, एच एम पी, ए आई आई ई ए और रेल, केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा और बैंक कर्मचारियों की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था।

१५ जनवरी १९७५ को दिल्ली बन्द रहा। बन्द में शामिल होने के लिए ए आई टी यू सी पहले राजी हुयी थी लेकिन अन्तिम क्षण में लचर बहाना बना कर वह पीछे हट गयी। मगर दूसरी ट्रेड यूनियनें आगे आयीं और बन्द आंशिक सफल रहा।

वेतन ज़ाम विरोधी अभियान के चलते देश भर में एक नये वायुमंडल का निर्माण हुआ है। मजदूर वर्ग के सामने उपस्थित आम समस्याओं पर संग्राम और एक देसव्यागी आन्दोलन की जरूरत को मजदूरों ने समझा है। इस एकता की रक्षा और इसे शक्तिशाली बनाने के लिये सारे प्रयास चलाने होंगे ताकि भविष्य में मजदूरों के संग्रामों का और अच्छी तरह समन्वय तथा मार्गदर्शन किया जा सके।

राज्य और स्थानीय स्तर पर अनेक संग्राम हुये हैं। आइये, एक के बाद एक राज्यों की समीक्षा हम करें जिससे यह जान जांय कि सम्बन्धित राज्य में आन्दोलन की किस हद तक अग्रगति हुई है।

पश्चिम बंगाल

पिछले दो वर्षों के दौरान, प० बंगाल में जारी आतंक राज्य ने औद्योगिक संबंधों की ढक रखा है। सी आई टी यू की लगभग तीन सौ यूनियनें अभी भी कांग्रेसी गुण्डों के कब्जे में हैं और इलाके में ट्रेड यूनियन का स्वाभाविक कामकाज असम्भव है। सबसे ज्यादा आतक बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र, आसनसोल-रानीगंज-दुर्गापुर अंचल तथा उत्तर बंगाल के चाय बगानों में फैलाया गया।

एरनाकुलम सम्मेलन के बाद जो दो राज्यव्यापी आम हड़तालें हुईं उनकी अन्य मांगों में एक माग "आतंक और गुण्डागर्दी की समाप्ति' थी। आतंक-ग्रस्त इलाकों में भी बन्द का असर पड़ा।

पहली आम हड़ताल २७ जुलाई १९७३ को हुई। जरूरी चीजों का दाम

घटाने, काटा गया राशन वापस देने, डी आई आर और मीसा खत्म करने, राजबंदियों की रिहाई आदि मांगों के लिए यह हड़ताल हुई। पहले सी आई टी यू की राज्य कमेटी ने इन सवालों पर एक दिन की आम हड़ताल की अपील की। लेकिन संयुक्त रूप से हड़ताल की घोषणा करने के बदले ए आई टी यू सी ने एकतरफा तौर पर २७ जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया। सी आई टी यू ने इस तारीख का समर्थन किया। लेकिन यू टी यू सी, यू टी यू सी (लेनिन शरणी) और टी यू सी सी हड़ताल में शामिल नहीं हुई। इस हड़ताल से मजदूरों में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि अगर वे एकजुट होते हैं और प्रतिरोध करते हैं तो आतंक को पराजित कर सकते हैं।

१७ नवम्बर १९७३ का दूसरा बंगाल बन्द और भी व्यापक था। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसका नतीजा खाद्य संकट कीमतों की अस्वाभाविक वृद्धि; राशन में कटौती आदि है, यह आम हड़ताल सी आई टी यू, यू टी यू सी, यू टी यू सी (लेनिन शरणी), टी यू सी सी और एच एम एस के संयुक्त आह्वान पर हुई। ९ वामपंथी दलों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया। इसके पूर्व, ए आई टी यू सी, आई एन टी यू सी और एच एम एस ने १७ नवम्बर को "काम बन्द" का आह्वान किया था। लेकिन बाद में उन्होंने यह तारीख दो दिन आगे बढ़ा दी ताकि आम हड़ताल में तोड़-फोड़ की जा सके। प० बंगाल सरकार ने बन्द के खिलाफ यद्यपि राजनीतिक रूप से लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बन्द का दमन करने के लिये उसने व्यापक तैयारी की। जनता को डराने धमकाने की पूरी आजादी कांग्रेसी गुण्डों को दे दी गयी।

३१ जनवरी १९७४ को हड़ताली चटकल मजदूरों के समर्थन में और १५ मई १९७४ को रेल मजदूरों के प्रति एकजुटता का इजहार करते हुये प० बंगाल के मजदूर वर्ग ने एक-एक दिन की हड़ताल की।

चटकल मजदूरों की ३३ दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। सरकार और जूटशाहों के संगठन आई जे एम ए की ओर से मजदूरों से जो वादे किये गये थे, उन पर अमल करने में वे संजीदा नहीं थे। बदली मजदूरों के संबंध में केन्द्रीय श्रममन्त्री ने जो राय दी, आई जे एम ए ने उसे लागू नहीं किया और कुछ मिल मालिक इसे रद्द करने के लिये अदालत में गये। प० बंगाल सरकार आई जे एम ए का खुला पक्षपात कर रही थी। इसके २४ दिसम्बर १९७४ को जूट उद्योग की यूनियनों ने एक दिन

की हड़ताल की।

इसी बीच प० बंगाल सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सुधार के सुझाव देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जिसके चेयरमैन प्रो० एस० भट्टाचार्य बनाये गये। कमेटी ने १९३९ के सूचकांक को १९६० के सूचकांक में बदलने के एक नये तरीके की सिफारिश की जिसके फलस्वरूप मजदूरों को प्रति महीने ६० रू० से लेकर १०० रू० तक अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मिला होता। लेकिन प० बंगाल सरकार ने डी आई ओर लागूकर इसे घटा कर १८ रू० तक कर दिया। इससे मजदूर काफी क्रोधित हो गये।

प० बंगाल में चटकल मजदूरों को ६ जनवरी १९७५ से एक और लगातार हड़ताल करनी पड़ी जिसमें सभी यूनियनें शामिल हुईं। जूटशाहों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लम्बी हुई लेकिन मजदूरों में उल्लेखनीय एकता कायम हुई थी। वे लम्बे संग्राम के लिये कमर कसे हुये थे।

जूटशाहों पर दबाव डालने के बजाय प० बंगाल सरकार ने बड़ी बेशर्मी से उनका समर्थन किया और खुलेआम मजदूरों के हितों के खिलाफ काम किया। इसी वजह से १०० घण्टे से भी अधिक की लम्बी समझौता वार्त्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और वास्तव में मजदूरों की कोई भी मांग नहीं स्वीकार की गई। १८ फरवरी से आई जे एम ए के आफिस के सामने १२ घंटा व्यापी सामूहिक धरना दिया गया जिसमें हज़ारों चटकल मजदूर और अन्य मजदूर कर्मचारी शामिल हुये। केन्द्रीय और राज्य सरकार, सौदागरी तथा जीवन बीमा के कर्मचारियों और सी आई टी यू की बहुत सी यूनियनों ने चटकल मजदूरों के प्रति एकजुटता जाहिर की। दूसरी ओर, हड़ताली मजदूरों की सहायता के लिये १० हजार से भी अधिक रुपया इकठ्ठा किया गया। यद्यपि आई एन टी यू सी भी हड़ताल की एक हिस्सेदार थी, लेकिन कांग्रेसी गुण्डों ने कमरहट्टी में चटकल मजदूरों की एक सभा नहीं होने दी। इस सभा के वक्ता ज्योति वसु थे। चटकल मजदूरों के समर्थन में १९ फरवरी को एस एफ आई ने जब हड़ताल की तो कांग्रेसी छात्रों ने एस एफ आई के कार्यकर्त्ताओं को मारा पीटा।

यद्यपि मजदूर हड़ताल जारी रखने को तैयार थे, लेकिन आई एन टी यू सी एच एम एस और एन एफ आई टी यू ने विश्वासघात कर २१ फरवरी को हड़ताल खत्म कर दी। इससे चटकल मजदूरों की कतारों में दरार पड़ गई। सी आई टी यू और अन्य ५ यूनियनों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया और परिस्थिति की समीक्षा करने के बाद, दो दिनों के बाद २३ फरवरी १९७५

को हड़ताल समाप्त कर दी गयी। इस तरह चटकल मजदूर बड़ी बहादुरी के साथ ४८ दिनों तक लड़ते रहे। चटकल मजदूरों के आन्दोलन के इतिहास में यह अब तक की सबसे लम्बी हड़ताल थी।

इंजीनियरिंग उद्योग में लगातार हड़ताल की नोटिश देने के बाद २५ जून १९७३ को एक समझौता हुआ। जिसके अनुसार मजदूरों की तलब में २५ रु० से लेकर ५० रु० तक की बढ़ोत्तरी हुई। अधिकांश प्रबन्धकों ने समझौते पर अमल नहीं किया। सरकार ने डी आई आर लागू कर न्यूनतम २०० रु० देने का आदेश दिया। लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। ए आई टी यू सी और आइ एन टी यू सी के विरोध के चलते कोई उद्योगवार कार्र-बाई नहीं की जा सकी। लेकिन कारखानों के आधार पर कई संग्राम हुये। इनमें जय इन्जीनियरिंग के मजदूरों का संग्राम उल्लेखनीय है। इस कारखाने के प्रबन्धकों ने पहले के समझौते को तोड़ते हुये मनमाना काम का अतिरिक्त बोझ लाद दिया। इसी के खिलाफ जय इन्जीनियरिंग के मजदूरों का संग्राम २३ अप्रेल १९७३ से शुरू हुआ, जो छः महीने तक चला। बड़े पैमाने पर छँटनी के खिलाफ और अपनी मांगों के लिये जी इ सी के ३५०० मजदूरों की हड़ताल भी लम्बी चली। उनकी यह हड़ताल २९ मई '७३ से शुरू हुई थी। इन मजदूरों को पुलिस जुल्म का मुकाबला करना पड़ा। समूचे गार्डेनरीच इलाके में इनके समर्थन में एकजुटता संग्राम चलाया गया। ५ नवम्बर १९७३ से बंगाल लैम्प के मजदूरों ने भी बड़ा संग्राम चलाया। यह संग्राम छँटाई और समझौते पर अमल न करने के खिलाफ चलाया गया। उन्होंने तालाबन्दी के खिलाफ भी लड़ाई की। इसी तरह रानीगंज के जे० के० अलमुनियम, शालीमार वर्क्स, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग, गेस्टकीन विलियम्स, हिन्द मोटर्स के मजदूरों के संग्राम भी लम्बे दिनों तक चले। ले आफ और तालाबन्दियों के खिलाफ हवड़ा की लघु इंजीनियरिंग यूनिटों के मजदूरों ने भी कई लड़ाइयां लड़ी।

तमाम चाय बगान यूनियनों की कोआर्डिनेशन कमेटी ने ६ अगस्त से लगा-तार हड़ताल का फैसला लिया, लेकिन प० बंगाल सरकार द्वारा वेतन कमेटी नियुक्त करने के बाद हड़ताल वापस ले ली गयी। बाद में सी आई टी यू की प० बंगाल राज्य कमेटी ने इसकी आलोचना की। लेकिन, चाय बगीचों के राष्ट्रीयकरण और बन्द चाय बगीचों को खोलने की मांग पर १४ जनवरी को उत्तर बंगाल के समस्त चाय बगानों में हड़ताल हुई। २१ फरवरी १९७४ को

स्वायत्तता और नेपाली भाषा की मान्यता देने की मांग पर पहाड़ी इलाकों के चाय बगानों में हड़ताल हुई।

इस दौरान दुर्गापुर के इस्पात मजदूरों ने कई बार हड़तालें की। स्टील मेल्टिंग शाप के मजदूरों के लिये बोनस स्कीम में सुधार की मांग पर २३ मार्च से २५ अप्रेल ७४ तक अलाय स्टील का काम काज ठप्प हो गया। अगुआ मजदूर कार्यकर्त्ता का० सुशान्त चक्रवर्त्ती की हत्या के खिलाफ २७ अगस्त को अलाय स्टील में फिर हड़ताल हुई। ३० दिसम्बर को दुर्गापुर इस्पात और अलाय स्टील के मजदूरों ने वेतन जाम के खिलाफ और छँटाई शुदा ठीका मजदूरों को फिर से बहाल करने की मांग के समर्थन में हड़ताल की। इस्पात संयंत्र के ७ हजार ठीका मजदूर तलब में वृद्धि के लिये लड़े और रोजाना मजूरी में १ रु० की बढ़ोत्तरी हासिल की। ठीकेदारों द्वारा गुण्डों की बहाली के खिलाफ भी उन्होंने संग्राम किया। इनमें से कुछ संग्रामों में ए आई टी यू सी और आई एन टी यू सी को शामिल होने के लिये बाध्य किया जा सकता था।

पथ-परिवहन उद्योग में हमारी यूनियनों के खिलाफ भयंकर गुण्डागर्दी की गई। राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से कलकत्ता स्टेट ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यूनियन की मान्यता रद्द कर दी और कांग्रेसी यूनियन को ला बिठाया। हमारे संगठकों और मजदूर कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ अधिकारियों ने चार्जशीट जारी किया और झूठे मुकदमे दायर किये। इतना होने पर भी, २६ मार्च और २३ सितम्बर १९७४ को अधिकारियों के तमाम बाधाओं को पार करते हुए हमारी यूनियन राइटर्स बिल्डिंग (सचिवालय) के सामने विशाल डेपुटेशन ले जाने में समर्थ हुई। १० जनवरी १९७४ को अपनी पुरानी मांगों के लिये कैरियर्स ट्रान्सपोर्ट ने सी आई टी यू के नेतृत्व में हड़ताल की कई संग्रामों के बाद उत्तर बंगाल ट्रान्सपोर्ट के मजदूर कुछ मांगें हासिल करने में सफल हुए।

प्रबन्धकों की तालाबन्दी की घोषणा के खिलाफ नेशनल रबर मैंन्युफैक्चरिंग कम्पनी के मजदूरों ने ६ महीने की लम्बी लड़ाई लड़ी। इनचेक टायर में भी लम्बा संग्राम हुआ। डनलप के मजदूरों ने एकजुटता जाहिर की।

हमारी यूनियनों द्वारा किये गये संग्रामों के कारण बन्दरगाहों में सी आई टी यू की स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई है। तलब, मँहगाई भत्ता आदि मांगों पर चीपिंग और पेन्टिंग के मजदूर ७० दिनों तक हड़ताल पर रहे और अन्ततः कुछ मांगें उन्होंने हासिल की। 'बन्दरगाह नाविकों के संग्रामी मोर्चे' का निर्माण—जो ११ यूनियनों का संयुक्त मोर्चा है—बन्दरगाह मजदूरों के

आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि एच एम एस और आई एन टी यू सी इस मोर्चे में शामिल नहीं हुई, फिर भी यह मोर्चा १० मई १९७४ को गोदी मजदूरों की सफल हड़ताल कराने में समर्थ रहा। आवश्यकता पर आधारित वेतन, नौकरी की सुरक्षा, बुनियादी तलब में मंहगाई भत्ते को मिलाने आदि मांगों के लिये यह हड़ताल हुई। इसके अलावा, अधिक बोनस की मांग करते हुये गोदी मजदूरों ने सफलता पूर्वक "नियमानुसार काम" आंदोलन चलाया नौकरी की सुरक्षा के लिये और सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ संग्रामों में किरानी और दरवान भी शामिल हुये।

राज्य कमेटी की पहल पर बीड़ी मजदूरों का एक सम्मेलन २७ और २८ अप्रेल '७४ को मुर्शिदाबाद में हुआ। सम्मेलन से एक मांग पत्र अपनाया गया। १० नवम्बर १९७४ को कलकत्ते में १० हजार बीड़ी मजदूरों की एक जबर्दस्त रैली हुई। प० बंगाल बीड़ी मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर २९ जनवरी १९७५ को राज्य भर में एक दिन की सफल हड़ताल हुई।

इन संग्रामों के अलावा, उद्योगवार और कुछ कारखानों के आधार पर भी संग्राम किये गये जिनमें कुछ तो एकजुट होकर लड़े गये। रानीगंज के बंगाल पेपर मिल के मजदूरों ने तालाबन्दी के खिलाफ ६ महीने का लम्बा संग्राय किया। संग्राम के दौरान ही कारखाने के अन्दर हमारे तीन मजदूरों की बर्बर हत्या कर दी गयी।

१९७३ में, तालाबन्दी के खिलाफ सात महीने तक संग्राम करने से बाद हुगली स्थित केशोराम रेयन के मजदूरों ने अपने वेतन में ६९ रु० की बढ़ोत्तरी हासिल की। लेकिन प्रबंधकों ने उन मजदूरों के खिलाफ प्रतिशोधक कदम उठाये जो भारी कठिनाइयों के बावजूद दिलेरी से लड़ रहे थे। मजदूरों को दो वर्ष का बोनस नहीं दिया गया है और बड़े पैमाने पर छँटनी की जा रही है। लिहाजा मजदूर एक और संग्राम की तैयारी कर रहे हैं।

दुर्गापुर के भारत ओप्थेलमिक ग्लास के मजदूरों ने अधिक वेतन की मांग पर हड़ताल की। प्रबन्धकों ने सी आई टी यू यूनियन के सचिव समेत १८ मजदूरों की छंटनी कर दी। लेकिन मजदूरों ने कुछ छंटनी आदेशों को वापस लेने पर प्रबन्धकों को बाध्य कर दिया। आठ मजदूरों को अभी भी काम पर नहीं लिया गया है। उनकी बहाली के लिये यूनियन संग्राम कर रही है।

तलब वृद्धि की मांग पर ९२ नगरपालिकाओं के ३० हजार मजदूरों ने १८ से २३ जुलाई १९७३ तक हड़ताल की। कलकत्ता कारपोरेशन के ३३ हजार मजदूरों ने भी १ अक्टूबर १९७४ से काम बन्द कर दिया। इन तमाम हड़तालों में सी आई टी यु की यूनियनें शामिल हुईं, हालांकि कुछ जगहों में हम शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन कांग्रेसी यूनियन ने मजदूरों के साथ गद्दारी की! कलकत्ता कारपोरेशन में उन्होंने दस घण्टे के बाद ही बिना कोई मांग प्राप्त किये ही एकतरफा तौर पर हड़ताल खत्म कर दी। फूट पड़ने के कारण अन्य यूनियनें हड़ताल न चला सकीं।

३३ सूती मांग के लिये बाटा शू कम्पनी के १३ हजार मजदूरों ने १८ दिनों तक हड़ताल की। मजदूरों की उल्लेखनीय एकता ने विदेशी प्रबन्धकों को ७३ रु० की तलब-बृद्धि स्वीकारने को बाध्य कर दिया।

रोप इंडस्ट्री के मजदूरों ने भी १५ से लेकर ३६ रु० प्रति महीने की वेतन बृद्धि हासिल की। सी आई टी यू और अन्य यूनियनों की संयुक्त संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चलाये गये एकजुट संग्राम के जरिये ही यह बढ़ोत्तरी हासिल की गई।

मूल्य सूचकांक में जालसाजी और बिजली संकट के खिलाफ ऐक्यबद्ध संग्राम खड़ा करने में राज्य कमेटी ने पहल की। अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ ही राज्य कमेटी के विशेषज्ञ कमेटी के पास एक सारपूर्ण ज्ञापन दिया, जिसमें मूल्य सूचकांक की धांधली का पर्दाफाश किया गया था। लेकिन कमेटी की सिफारिशों को बेअसर बनाने के लिये सरकार ने उस पर डी आई आर लागू कर दिया तथा जूटशाहों के बेशर्म पैरोकारों की तरह शिमला लेबर ब्यूरो का डायरेक्टर धांधलियों पर पर्दा डालने के लिये आगे आया।

१९७३–७४ के दौरान बिजली संकट के सबसे ज्यादा शिकार प० बंगाल के मजदूर हुए। बिजली कटौती के कारण १९७३ में १५५३ कारखानों के ६,४५,३२४ मजदूरों को ले–आफ किया गया। इसी वजह से १९७४ में कुछ कारखानों में उत्पादन ६० प्रतिशत कम हुआ। इस साल के प्रथम पांच महीनों में ही, २ लाख ७० हजार मजदूरों को ले-आफ किया गया। राज्य कमेटी ने मांग की कि बिजली कटौती के कारण पूरा हरजाना मजदूरों को दिया जाय। उसने यह भी बताया कि किस तरह बिजली की राशनिंग बिजली संकट का समाधान नहीं कर सकती। राज्य कमेटी की पहल पर, राज्य में मजदूर वर्ग का एक आम मोर्चा बनाने के लिये अन्य ट्रेड यूनियनें भी एकजुट हुईं।

केरल

केरल सी आई टी यू ने १९७३ के मध्य में दो बड़ी हड़तालें की । १० जुलाई को, केरल राज्य सी आई टी यू के आह्वान पर हुये बन्द में मजदूर वर्ग और श्रमजीवियों के दूसरे हिस्से एकजुट रूप से शामिल हुये। विकट खाद्य संकट और भुखमरी के खिलाफ तथा रोजाना १२ औंस राशन की मांग पर यह बन्द हुआ । ५ लाख से अधिक मजदूरों ने बन्द में हिस्सा लिया । इसके तीन सप्ताहों के अन्दर ही २ अगस्त को ऊंची कीमतों के खिलाफ और रोजाना १२ औंस राशन की मांग पर एक और सफल बन्द किया गया । भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मा०) और विपक्ष के अन्य दलों, सी आई टी यू और दूसरे जन संगठनों ने इस बन्द का आह्वान किया था। बन्द का दमन करने के लिये अच्युत मेनन मंत्रिमण्डल ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। पुलिस की गोली वर्षा में २ मजदूरों की मौत हो गई और दो बुरी तरह घायल हो गये। बेहिचक लाठी चार्ज तो उस दिन की आम बात थी । बन्द से पहले ही ५००० से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और बन्द के दिन और हजारों व्यक्ति पकड़े गये । लेकिन इन तमाम दमनात्मक व्यवस्थाओं के बावजूद बन्द शानदार रूप से सफल हुआ, जो अच्युत मेनन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की राय का इजहार कर रहा था ।

३-४ सितम्बर की आधी रात से पथपरिवहन मजदूरों के हड़ताल पर चले जाने से समूचे केरल राज्य ट्रान्सपोर्ट ठप्प हो गया । सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, आई एन टी यू सी तथा ४ अन्य यूनियनों के आह्वान पर यह हड़ताल हुई । ११.५ प्रतिशत बोनस के सरकारी फैसले की जगह मजदूर प्रतिनिधि १४.५ प्रतिशत की मांग कर रहे थे । अखबारों की खबरों के अनुसार, शासक पार्टियों की तालमेल कमेटी की बैठक में मुख्यमन्त्री अच्युत मेनन ने घोषणा की कि यदि परिवहन मजदूरों को ११.५ प्रतिशत से अधिक बोनस दिया गया और यदि १३ सितम्बर के पूर्व बसों का चलना शुरू नहीं हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे । आई एन टी यू सी तथा ए आई टी यू सी के नेतृत्व पर दबाव डाला गया और वे हड़ताल से अलग हट गये । लेकिन मजदूरों ने काम पर जाने से इनकार कर दिया और २० दिनों तक मुकम्मिल हड़ताल चलती रही । आखिर में, सरकार को झुकना पड़ा । अधिक बोनस की मांग माननी पड़ी तथा इसके साथ ही उसने १२ दिन की तलब पेशगी के तौर पर दी ।

इन हड़तालों के साथ ही साथ, मेहनतकशों के सभी हिस्सों ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ीं। १९७३ के खत्म होने के पहले, राज्य विद्युत बोर्ड, ग्वालियर रेयन, त्रावनकोर इलेक्ट्रिकल केमिकल, रबर ट्रेपर्स वायनड काफी बगीचा, नौका निर्माण स्पीनिंग मिल, सरकारी कालेजों के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी, जहाज के खलासियों, लारी ड्राइवर और खलासियों, क्वायर मजदूरों ने हड़-ताल और लगातार हड़तालें कीं। संक्षेप में सभी तबके को हड़ताल संग्राम के मैदान में खींच लाया गया था। इनमें अधिकांश संग्राम सी आई टी यू के नेतृत्व में हुये, जबकि बहुत से संग्राम सी आई टी यू और अन्य यूनियनों द्वारा भी संयुक्त रूप से चलाये गये।

लगातार बदतर होती खाद्य परिस्थिति के कारण मजदूर वर्ग को एक बार फिर रास्ते पर उतरना पड़ा। ५ विरोधी दलों, सी आई टी यू और अन्य जन संगठनों के आह्वान पर २१ दिसम्बर को शानदार सफल आम हुई। १२ औन्स राशन, कीमत घटाने तथा पुलिस जुल्म बन्द करने की मांग पर यह हड़ताल हुई। हड़ताल के पहले सरकार ने ५०० सी आई टी यू कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया और पुलिस ने कई स्थानों पर लाठी चलाई। इसका सिर्फ यह परिणाम हुआ कि अपने नेताओं के विरोध के बावजूद बहुत से कार-खानों में ए आई टी यू सी और आई एन टी यू सी के समर्थक मजदूरों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। इससे पहले ९ नवम्बर को सी आई टी यू की राज्य कमेटी के आह्वान पर ट्रेड यूनियन मामलों में पुलिस की दखलदांजी और मूल्य वृद्धि के खिलाफ समूचे राज्य में प्रदर्शन किये गये।

केरल सरकार का एक और मजदूर वर्ग विरोधी कदम था। राज्य में नारियल मजदूरों की न्यूनतम तलब लागू न करना और हजारों मजदूरों की नौकरी पर भारी खतरा पैदा करते हुये इस उद्योग में नारियल के रेशे की कुटाई के लिये मशीन लगाना। इस नीति के विरोध में १ नवम्बर १९७३ को त्रिवेन्द्रम जिले के १ लाख नारियल मजदूरों ने हड़ताल की। इसी तरह, १५ नवम्बर को, क्वीलन जिले के सवा लाख नारियल मजदूरों ने हड़ताल की और ५ हजार मजदूरों ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आई एन टी यू सी और यू टी यू सी को हाथ लाने में सी आई टी यू ने पहल की और १५ जनवरी १९७४ को ५ लाख नारियल मजदूरों की एकजुट राज्य-व्यापी हड़ताल हुई।

न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति ने जो सिफारिशें की थीं, राज्य सरकार

उन्हें बगीचा उद्योग में लागू करने से इन्कार कर दिया। इससे बगीचा मजदूर तबाह हुये। इसका विरोध करते हुये एक लाख बगीचा मजदूरों ने ८ फरवरी १९७४ को राज्य भर में हड़ताल की। सी आई टी यू और एच एम एस के आह्वान पर यह हड़ताल हुई। कोट्टायम और इड्डीकी जिले के रबर, चाय, काफी तथा इलायची के बगीचों के मजदूरों ने गांवों के सरकारी दफ्तरों पर पिकेटिंग की। इरूमाला मुंडाक्कायम, होशदुर्ग, तालीपरमा तथा तेलीचेरी में भी इसी तरह पिकेटिंग की गई। अत्याचारों के विरोध में भी बगीचा मजदूरों हड़ताल की। कोहुमेन और चंदनपल्ली स्टेट के १० हजार मजदूरों ने लाठीचार्ज के विरोध में २३ जनवरी १९७४ को हड़ताल कर दी। अपने अंचल के सी आई टी यू नेता का० एम० एन० भास्करन की निर्मम हत्या की निन्दा करते हुये कोनडाझी के बगीचा मजदूरों और खेत मजदूरों ने १ फरवरी १९७४ को हड़ताल की।

शोचनीय जीवन दशा के कारण खपड़ा मजदूर भी संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर हुये। २ नवम्बर १९७३ को सी आई टी यू और आई एन टी यू सी ने संयुक्त रूप से २ रु० रोजाना मजूरी वृद्धि की मांग करते हुये सफल हड़ताल की। ओल्वाकोडे के कामनवेल्थ खपड़ा (टोइल) फैक्टरी के मज़दूरों का संग्राम बड़ा लम्बा था। इन संग्रामरत मज़दूरों के समर्थन में १० फरवरी को पालघाट जिले के तमाम खपड़ा मज़दूरों ने हड़ताल की।

सी आई टी यू ने खेतिहर मजदूरों के संग्राम भी चलाये। इनमें पालघाट के कृषि विश्वविद्यालय के कृषि और पशु पालन विभाग की हड़ताल उल्लेखनीय थी। राज्य सरकार के अधीन के १० हजार फार्म मजदूर १५ नवम्बर १९७३ से हड़ताल पर चले गये। उनकी मांगें थी; अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण, अन्तरिम राहत, प्राविडेण्ट फण्ड आदि। यूथ कांग्रेसी गुण्डों के हमलों और ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिवाद करते हुये ८ दिसम्बर १९७३ को अलेप्पी जिले के खेत मजदूरों ने हड़ताल की।

केरल सरकार की न्यूनतम मजूरी विज्ञप्ति को लागू करवाने के लिये तीन लाख बगीचा मजदूरों को जून तथा अगस्त १९७४ में दो-दो हड़तालें करनी पड़ी। केरल सरकार के न्यूनतम मजूरी अध्यादेश के खिलाफ बगीचे के प्रबंधकों ने अदालत में याचिका दाखिल की। इस याचिका के विरोध में जून महीने में तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से एक दिन की हड़ताल की।

मजदूरों ने जब यह देखा कि अध्यादेश द्वारा की गई मामूली वृद्धि को

बगीचा मालिक अब भी देना नहीं चाह रहे हैं, तो उन्होंने अगस्त १९७४ में लगातार हड़ताल का रास्ता पकड़ा। यह हड़ताल ३८ दिनों तक चली। आखिर में मालिकों को झुकना पड़ा और झक मार कर समझौता करना पड़ा, जिसके अनुसार, चाय बगीचा के मजदूरों के लिये १.२० रु०, रबर बगीचे के लिये १.६८ रु०, इलायची के लिये १.३४ रु० और काफी मजदूरों के लिये १.३२ रु० की दैनिक मजूरी में अतिरिक्त वृद्धि हुई।

१९७४ के दौरान, नारियल के रेशे और हथकरघा उद्योग के मजदूरों ने अनगिनत संग्राम किये। अगस्त महीने में, अधिक मजदूरी और बोनस की मांग पर क्वीलन जिले के ७५ हजार रेशा मजदूरों ने सी आई टी यू के नेतृत्व में बेमुद्दत हड़ताल की। इसी महीने में कन्नानोर ज़ोन के ७५ हजार हथकरघा मजदूर भी बोनस की मांग पर लगातार हड़ताल पर चले गये। अलेप्पी और त्रिवेन्द्रम के रेशा मजदूरों और कालीकट जोन के हथकरघा मजदूरों ने भी कई संग्राम किये। इसके अलावा, इन्हीं जगहों के टेक्सटाइल, इन्जीनियरिंग, काजू बीड़ी खपड़ा, तथा और दूसरे उद्योग के मजदूरों द्वारा भी कई संग्राम किये गये। हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन लि० ने १२०० मजदूरों की छंटाई कर दी। इसका प्रतिवाद करते हुये इडीक्की प्रोजेक्ट के ४५०० मजदूरों ने हड़ताल की।

दूसरी उल्लेखनीय हड़ताल फैक्ट (एफ ए सी टी) कोचीन डिवीजन के मजदूरों की हड़ताल थी, जो जीत हासिल करने के बाद समाप्त हुई। प्रबन्धकों ने १०० रु० प्रति महीने की वेतन बढ़ोत्तरी स्वीकार ली। उन्होंने यह भी वादा किया कि हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी को सजा नहीं दी जायेगी।

अपनी जरूरी मांगों के लिये त्रिचूर जिले के पथ-परिवहन मजदूरों पंथालम की मौनम चीनी मिल के मजदूरों, कालीकट के नगरपालिका मजदूरो, शिपयार्ड के निर्माण मजदूरों ने भी हड़ताल की।

१० दिसम्बर १९७४ को केरल की जनता द्वारा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसके चलते केरल में राशनिंग व्यवस्था चरमरा गई, एक और आम हड़ताल की गई। यद्यपि पुलिस जुल्म और गुण्डागर्दी को और तेज किया गया, लेकिन हड़ताल से समूचे राज्य में औद्योगिक गतिविधियां और नागरिक जन-जीवन एकदम ठप्प हो गया। यह बन्द विरोधी पार्टियों की एक्शन कमेटी के आह्वान पर हुआ।

सबसे डटकर लड़े गये संग्रामों में कालमासेरी (कोचीन) स्थित भारत रेयर

अर्थस् मजदूरों की १२५ दिनसीय हड़ताल का उल्लेख अवश्य करना होगा। वेतन और मंहगाई भत्ते के सवाल पर यह हड़ताल हुई। प्रबन्धकों ने चाहा कि २७५ रुपये पर मंहगाई भत्ते की हदबंदी कर दी जाय, लेकिन इस प्रस्ताव को तमाम यूनियनों ने ठुकरा दिया। आखिकार, मजदूरों की एकता को देखकर प्रबन्धक वेतन में १२.५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने पर मजबूर हुए और महँगाई भत्ते की हदबन्दी वापस ले ली गई। एक संयुक्त जनरल बाडी मीटिंग में मजदूर जब सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये तब २० जनवरी १९७५ को हड़ताल खत्म कर दी गई। इससे पहले रेयर अर्थ मजदूरों के समर्थन में तमाम यूनियनों द्वारा अलपाई-इलूर-कालमाडेरी इलाके में आम हड़ताल की योजना बनाई गई थी।

प्रबंधकों के इशारे पर सी आई एस एफ ने रिगवर्क के मजदूरों पर भयंकर लाठी चार्ज किया। मजदूरों ने अपने कुछ छंटाई शुदा साथियों की फिर से बहाली के लिये २१ दिसम्बर को हड़ताल की थी। इस लाठी चार्ज के कारण महिलाओं समेत २२ मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। ज्यों ही इस लाठी चार्ज की खबर कोचीन शिपयार्ड के मजदूरों तक पहुंची, समूचा शिपयार्ड ठप्प हो गया।

परमबवूर के त्रावनकोर रेयन के २००० मजदूर ४ जनवरी १९७५ से बेमुद्दत हड़ताल पर चले गये। वे १९७३ के बोनस की मांग कर रहे थे। न्यूनतम मजूरी अध्यादेश को लागू करने की मांग करते हुये थालीकुलम, अंथीकाड, मनलूर पंचायतों के मजदूरों ने १५ दिसम्बर से अनिश्चित कालीन हड़ताल की।

तमिलनाडु

सी आई टी यू के दूसरे सम्मेलन के बाद, १३ दिसम्बर १९७३ का राज्य-व्यापी बंद तमिलनाडु के मजदूर वर्ग और जनता की सबसे व्यापक कार्रवाई थी। बन्द का आह्वान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०), दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी, ए डी एम के, सी आई टी यू और अन्य दूसरे जन संगठनों ने किया था। बन्द पूरा सफल रहा। यह बन्द राज्य और केन्द्रीय सरकारों जन विरोधी नीतियों के विरोध में किया गया था जो मूल्य वृद्धि बेकारी, बिजली की कटौती तथा जनता की अन्य कठिनाइयों के लिये जिम्मेदार थी। लेकिन, ए डी एम के और दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की

योजना बनाई और केन्द्रीय सरकार को पाक-साफ का सर्टिफिकेट दे दिया। डी एम के सरकार ने यद्यपि ८ हजार नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया और जनता के खिलाफ बेहद गुण्डागर्दी की, लेकिन राज्य भर में बन्द को नहीं रोका जा सका।

१९७४ में पूरे राज्य में टेक्सटाइल मजदूरों के संग्राम का उल्लेख हमने पहले ही किया है। इसके अलावा टेक्सटाइल उद्योग में और भी दूसरे सग्राम हुये। इस राज्यव्यापी हड़ताल के पहले विभिन्न स्थानीय और कारखाने-वार हड़तालें हुई जिनमें ज्यादातर समस्त ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से की गईं। इन स्थानीय संग्रामों से ही मजदूरों को यह सबक मिला कि सिर्फ एक विस्तृत राज्यव्यापी कार्रवाई से ही उनकी मांगें मानने को कारखानेदारों पर पर्याप्त दबाव डाला जा सकेगा। मिल के अधिकारियों द्वारा मजदूरों पर हमले के खिलाफ मदुराई मिल्स के साढ़े सात हजार मजदूरों ने ३ जून १९७३ को हड़ताल की।

हथकरघा और पावरलूम के मजदूर अपनी बिगड़ती हालत के कारण संघर्ष में उतरे। ५ प्रतिशत तलब-वृद्धि और ३० नवम्बर १९७३ से की गई तालाबन्दी खत्म करने की मांग पर नागरकोयल के सात हजार हथकरघा मजदूरों की हड़ताल भी लम्बी लड़ाई थी। हड़तालो मजदूरों के प्रति एकजुटता भी ज़ाहिर की गई। सी आई टी यू की स्थानीय यूनियनों ने एक संयुक्त एक्शन कमेटी का गठन किया। ११ जनवरी १९७४ से वेतन-वृद्धि की मांग पर साउथ मदुराई के २ हजार मजदूर सी आई टी यू के झंडे के नीचे हड़ताल पर चले गये। २४ जनवरी को यह हड़ताल तब खत्म हुई जब मालिक ने तलब में कुछ वृद्धि की। इससे पहले, १५ दिसम्बर १९७३ से वेलोर के हथकरघा मजदूरों ने तलब में ५० प्रतिशत की वृद्धि और १५ प्रतिशत बोनस की मांग पर हड़ताल की। हड़ताल के दौरान डी एम के सरकार ने ५०० मजदूरों को गिरफ्तार किया, लेकिन मजदूरों की एकता को देखकर आखिर में मालिक ने उनकी अधिकांश मांगें मान ली और १ जनवरी १९७४ को हड़ताल खत्म हुई। मद्रास और अन्य केन्द्रों के पावरलूम मजदूर जनवरी ७४ से लेकर २ महीने तक हड़ताल पर रहे। वे मंहगाई भत्ते में प्रति प्वायंट १५ पैसे की वृद्धि की मांग पर लड़ रहे थे। ३ सौ से भी ज्यादा मजदूरों को हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किया गया।

निरंतर संग्रामों के जरिये बीड़ी मजदूरों ने कुछ मांगें हासिल की। १९७३

में सालेम के बीड़ी मजदूरों ने प्रति हजार बीड़ी पीछे २० पैसे का बोनस वसूला। मद्रास के हजारों बीड़ी मजदूरों द्वारा १८ जून १९७३ को एक दिन की हड़ताल की गई। उनकी मांगें थी : प्रति १००० बीड़ी की न्यूनमम मजूरी ५.५० रु०, सूचकांक में बृद्धि के प्रति प्वायंट पर १ पैसा मंहगाई भत्ता और ७ रु० प्रति मजदूर रोजाना मजूरी की गारंटी। समूचे राज्य के एक लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर, और बीड़ी सिगार एक्ट लागू करने, ५.७५ रु० न्यूनतम मजूरी, मूल्य सूचकांक से मँहगाई भत्ते को जोड़ने और बोनस की मांग पर ९ अप्रैल लगातार हड़ताल पर चले गये। हालांकि सी आई टी यू, ए आई टी यू सी और डी एम के यूनियनों को लेकर एक संयुक्त एक्शन कमेटी बनाई गई थी, पर ए आई टी यू सी मैदान छोड़कर भाग गई। फिर भी हड़ताल तब तक चलती रही जब तक मालिक कुछ मांगें स्वीकार करने पर राजी न हुये।

चीनी मजदूर भी पीछे न रहे। ५० प्रतिशत बोनस की मांग पर ३१ दिसम्बर १९७३ को चीनी मिलों के सब के सब मजदूर हड़ताल पर चले गये। मुकम्मिल हड़ताल हुई। २ जनवरी १९७४ को वेतन का ४३ प्रतिशत बोनस के रूप में देने को मालिक बाध्य हुये। मजदूरों की ओर से सी आई टी यू ने समझौते पर दस्तखत किया। इसी तरह कोठारी सुगर मिल के मजदूरों ने १ फरवरी १९७४ से छंटनी बन्द करने और तलब बढ़ाने की मांग पर हड़ताल की। आइ एन टी यू सी और एच एम एस द्वारा एक विश्वासघातक समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने पर मदुराई सुगरत मिल्स के मजदूरों ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया। इसके बाद प्रबन्धकों द्वारा १३ मजदूरों पर कारण बताओ नोटिश जारी की गई, जिससे बाध्य होकर मजदूरों को 'बैठकी हड़ताल' का रास्ता पकड़ना पड़ा। इसके बाद प्रबन्धकों ने तालाबन्दी कर दी। मगर मजदूर संग्राम चलाते रहे। नेलीकुप्पम सुगर मिल के प्रबन्धकों ने एक कठपुतली डी एम के यूनियन को चोरी चुपके मज़दूरों पर लादने की कोशिश की। इसका विरोध करते हुये इस चीनी मिल के २३०० मज़दूरों ने २२ जून १९७३ से "बैठकी हड़ताल" की। सी आई टी यू के यूनियन आफिस पर गुंडों ने हमला किया। लेकिन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले पुलिस ने सी आई टी यू के आफिस को ही बन्द कर दिया और यूनियन के काम काज करने पर रोक लगा दी गई।

अपनी मांगों के लिये राज्य के २५ हजार से भी ज्यादा नगरपालिका और सफाई मजदूरों ने ११ जुलाई १९७४ को सांकेतिक हड़ताल की। मजदूरों का

नेतृत्व देने के लिये सी आई टी यू और ए आई टी यू सी की यूनियनों को लेकर एक समन्वय समिति बनाई गयी। मद्रास कारपोरेशन और कुछ अन्य बड़ी नगरपालिकाओं में काम काज बिल्कुल ठप्प हो गया। अन्त में भत्ते में १२ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मजदूरों ने हासिल की

नेभेली की लिगनाइट खान के मजदूरों की १६ अप्रेल १९७४ की हड़ताल के साथ आखिकार ए आई टी यू सी और अन्य नेताओं ने दगा किया। यद्यपि, ३३८ रु तलब की मांग के लिये ६ यूनियवों की एक संयुक्त कमेटी का गठन इस समझ के आधार पर किया गया था कि कोई भी यूनियन इससे कम पर समझौता नहीं करेगी, लेकिन हड़ताल के ठीक पहले ए आई टी यू सी और डी एम के ने ३१२ रु स्वीकार लिया और हड़ताल की नोटिस वापस ले ली। मगर अन्य यूनियनें हड़ताल चलाती रहीं। मद्रास की पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार किये गये, लेकिन ए साई टी यू सी ने इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। इस दमन और फूट के बावजूद हड़ताल जारी रही, आई एन टी यू सी और ए डी एम के में भी ढुलमुलपन देखा गया और वे मैदान छोड़कर भाग गईं। सी आई टी यू के लिये केवल खुद की ताकत पर हड़ताल चलाना सम्भव न हुआ और अन्त में हड़ताल वापस लेनी पड़ी।

१५ अक्टूबर १९७३ से शुरू हुई कन्या कुमारी के राज्य परिवहन मजदूरों की हड़ताल भी एक लम्बी लड़ाई थी। २२५ मजदूरों को फिर से बहाल करने और अन्य मुद्दों पर अपने वादे से राज्य सरकार मुकर गई। सी आई टी यू की राज्य कमेटी की ओर से सहायता फण्ड इकट्ठा करने का आह्वान किया गया जिसमें विभिन्न यूनियनों ने चन्दा दिया।

पांच सूत्री मांगों के लिये १५ जून १९७३ को बिजली मजदूरों द्वारा ५० केन्द्रों के बोर्ड आफिसों पर राज्यव्यापी धरना दिया गया। मद्रास कोका कोला फैक्टरी (जिसकी मालिक भूतपूर्व राष्ट्रपति वी० वी० गिरि की बेटी है) के ट्रान्सपोर्ट और बोतल भरने वाले मजदूरों ने १५ जून १९७३ से मुअत्तली और मजदूरों की धर-पकड़ के खिलाफ लगातार हड़ताल शुरू की।

सी आई टी यू के बढ़ते प्रभाव से डी एम के सरकार आतंकित हो गयी और सी आई टी यू के नेताओं और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं पर उसने गुण्डों से हमले कराये। डी एम के गुण्डों ने हमारी जनरल कौंसिल के सदस्य का० वी० पी० चिन्तन पर जानलेवा हमला किया। यह तो सिर्फ का० चिन्तन की बेमिसाल हिम्मत और उपस्थित बुद्धि थी जिसकी बदौलत उनकी जान बच गयीं।

इस जाघन्य हमले से मजदूरों में गुस्से की लहर दौड़ गई और इसके विरोध में मद्रास की औद्योगिक इकाइयों के एक लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कोयम्बटूर, मदुराई, त्रिची आदि केन्द्रों के ए आई टी यू सी और ए डी एम के के मजदूर भी विरोध कार्रवाइयों में शामिल हुए।

इन तमाम संग्रामों में सी आई टी यू ने सक्रिय हिस्सा लिया और एकता के निर्माता के रूप में सी आई टी यू सामने आया। इस दौर में अपनी वर्ग सहयोगवादी भूमिका के कारण ए आई टी यू सी और भी अधिक तेजी से विछिन्न हुई।

महाराष्ट्र

एरनाकुलम सम्मेलन के बाद महाराष्ट्र और बम्बई में ६ आम हड़तालें और बन्द हुये, जो राज्य के मजदूरों के लड़ाकू तेवर को दर्शाते हैं।

सी आई टी यू के सम्मेलन के फौरन बाद ही राज्य कमेटी ने अकालग्रस्त किसानों के प्रति सरकारी नीति और बढ़ती कीमतों के खिलाफ अभियान चलाने में पहलकदमी की। सी आई टी यू, ए आई टी यू सी और सर्व श्रमिक संघ (लाल निशान ग्रूप) के आह्वान पर १५ मई १९७३ को बम्बई-थाना-अम्बरनाथ अंचल के ५ लाख मजदूरों ने हड़ताल की। बन्द पूर्ण सफल रहा। बन्द के दिन ही २५ हजार मजदूरों का विराट जुलूस निकला, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया।

एच एम पी और एच एम एस की यूनियनें इस हड़ताल में शामिल नहीं हुई और उन्होंने अलग से २५ मई को हड़ताल का आह्वान किया। चूंकि यह हड़ताल भी उन्हीं सब मांगों के लिये की गई थी इसलिये सी आई टी यू ने इसका विरोध नहीं किया।

२ जनवरी १९७४ को मुकम्मिल महाराष्ट्र बन्द हुआ जिसमें २ लाख से भी अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। बन्द का आह्वान महिलाओं की मूल्य-वृद्धि विरोधी कमेटी के साथ ही साथ वामपंथी दलों और सी आई टी यू, ए आई टी यू सी एच एम एस, एच एम पी, सर्व श्रमिक संघ और दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों ने किया था। जरूरी चीजों की ऊँची कीमतों के खिलाफ और प्रति व्यक्ति १२ किलो राशन की मांग पर यह बन्द किया गया था। शिव सेना के गुण्डों की मदद से एक सरकारी बन्द आयोजित कर महाराष्ट्र सरकार

ने जनता को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन इस काम में सरकार को सफलता नहीं मिली।

महाराष्ट्र में ३ मई १९७४ को एक सम्पूर्ण बंद के जरिये राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। यह एकजुट कार्रवाई थी और इससे समूचे राज्य का जन-जीवन ठप्प हो गया था।

इन हड़तालों के साथ ही, २५ दिसम्बर १९७३ को प्रति महीने प्रति व्यक्ति १२ किलो राशन की मांग पर नागपुर बन्द मनाया गया। सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, एच एम एस तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर यह बन्द किया गया। यह बन्द इस कदर कामयाब रहा कि उस दिन एक भी ट्रेन शहर से नहीं गुजर सकी

इस दौरान, सी आई टी यू के नेतृत्व में बहुत से लम्बे संग्राम हुये इनमें कैलिको केमिकल्स के मजदूरों की हड़ताल उल्लेखनीय है। यह हड़ताल १० अगस्त १९७३ से शुरू हुई और महीनों चलती रही। राज्य श्रम मन्त्री ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। विवाद में आश्चर्य की बात यह थी कि प्रबन्धकों ने ट्राइबूनल की १९७१ की राय को लागू करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मार्के की बात यह है कि खुद ट्राइबूनल ने ही ६ वर्षों के बाद यह राय दी थी। यूनियन स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को मुअत्तल कर दिया गया। हड़ताल का फौरी कारण यही था। प्रबन्धकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले, सरकार ने मजदूरों का दमन किया, दर्जनों मजदूरों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जमानत नहीं दी गई। पुलिस हाजत में उन पर अत्याचार किया गया। यहां तक कि सी आई टी यू की जनरल कौंसिल के सदस्य का० इ० एफ० एक्स० परेरा को भी गिरफ्तार किया गया और कत्ल के झूठे मुकदमें में उन्हें फांस दिया गया अभी भी कई मजदूर जेल में बन्द हैं। इन पर हत्या का झूठा मुकदमा है।

बरदाई प्रा० लि० के मजदूरों का संग्राम भी जो ५०३ दिनों तक चला, सी आई टी यू के झंडे तले लड़ा गया। आखिरकत, प्रबंधक मजदूरों की मांगें—तमाम मजदूरों की नौकरी की धारावाहिकता, ९९ छंटाईशुदा मजदूरों की फिर से बहाली, हड़ताल के दिनों का २५ प्रतिशत वेतन—मानने को बाध्य हुए।

सी आई टी यू के आह्वान पर ९ नवम्बर १९७३ को २०० कारखानों के के ४५००० मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। उन्होंने यह काम बन्द कैलिको,

बरदाई तथा सन-एन-सैंड के ४०० मजदूरों के समर्थन में किया, जो लम्बी हड़ताल पर थे।

अपने यूनियन नेता की मुअत्तली और २० मजदूरों को चार्जशीट दिये जाने के खिलाफ सीएट टायर के १२०० मजदूरों ने हड़ताल की। यह हड़ताल १२ नवम्बर १९७३ से शुरू हुई। राज्य श्रममन्त्री के समझौते के प्रस्ताव को भी प्रबन्धकों ने मानने से इनकार कर दिया, जिससे हड़ताल लम्बी हुई। अन्त में प्रबन्धकों द्वारा कुछ मांगें मानने के बाद ही ११ मार्च १९७४ को हड़ताल खत्म हुई।

सात दिन का हफ्ता लादने के खिलाफ बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों ने सफल संग्राम किया। प्रबंधकों के साथ आई एन टी यू सी ने एक समझौता कर लिया, लेकिन आम साप्ताहिक छुट्टी के मजदूरों के अधिकार को स्वीकार करने के लिये २ लाख टेक्सटाइल मजदूरों ने १५ और २२ जुलाई १९७३ को हड़ताल की हड़ताल इस कदर सफल हुई कि सरकार को यह प्रस्ताव रद्द करना पड़ा मजदूरों की एकता ने यह साबित कर दिया कि विश्वासघातक समझौते को पूरी तरह धूल चटाया जा सकता है।

२५ फरवरी १९७४ को ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बार्रवाई कमेटी, जिसमें आई एन टी यू सी को छोड़कर सभी यूनियनें शामिल थीं, की ओर से महाराष्ट्र विधान सभा का जबर्दस्त घेराव किया गया। यह घेराव बढ़ती कीमतों, चीजों का अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, पुलिस जुल्म और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया।

थाना औद्योगिक अंचल में जे० के० केमिकल्स के मजदूर आई एन टी यू सी नेतृत्व की गद्दारी के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन से खफा होकर आई एन टी यू सी के मठाधीश दत्ता सामंत ने जाली हड़ताल का आह्वान किया। सी आई टी यू के कार्यकर्त्ताओं पर यह झूठा अभियोग लगाकर कि उन्होंने आई एन टी यू सी के झंडे को जलाया है, वे उनको मुअत्तल करने की मांग कर रहे थे। जब मजदूरों ने उनके हड़ताल के आह्वान' को टायं टायं फिस कर दिया, तो आई एन टी यू सी के गुण्डों को मजदूरों के पीछे लगा दिया गया। सी आई टी यू के मजदूर कार्यकर्त्ताओं के घरों पर हमले किये गये और का० तिलकधारी की बर्बर हत्या कर दी गई। कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले महाराष्ट्र सरकार ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी। सी आई टी यू ने अन्य औद्योगिक मजदूरों को लेकर एकजुटता

संग्राम खड़ा किया। और आक्रान्त मजदूरों की रक्षा की।

अन्य संग्रामों में, हसरवाल इन्जीनियरिंग वर्क्स, गांधी इन्जीनियरिंग वर्क्स, एलकोर्ट फाउण्ड्री और प्रिसीसियन डाई कास्ट के मजदूरों की हड़तालें बेहद उल्लेखनीय है। इन संस्थानों में मजदूरों ने तीन महीने तक संग्राम किये और मांगें हासिल की। पावरलूम और होटल मजदूरों ने भी लड़कर कुछ सुविधाएं प्राप्त की।

सी आई टी यू के नेतृत्व में बम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद में टाइम्स आफ इंडिया के ४०० मजदूरों ने २२ अगस्त १९७४ को हड़ताल की। वे मंहगाई भत्ते में बृद्धि की मांग कर रहे थे। बम्बई के मजदूरों ने १९ सितम्बर को मैनेजर का घेराव किया और रोजाना १ घण्टा काम बन्द आन्दोलन चलाते रहे। अंत में मालिक ५० रु० की बढ़ोत्तरी प्रति महीने प्रति मजदूर करने पर बाध्य हुये। इस दौरान फ्री प्रेस जनरल के मजदुरों को दो-दो बार हड़ताल के रास्ते जाना पड़ा। एक बार तो तब, जब प्रबन्धक ने तालाबन्दी की। बातचीत के जरिये यह मामले का निपटारा हुआ। दूसरी हड़ताल २३ दिसम्बर १९७४ को तब हुई जब श्रमजीवी पत्रकारों के अखिल भारतीय फेडरेशन के अध्यक्ष और सह सम्पादक का० एस० बी० कोल्ये को मालिक ने मुअत्तल कर दिया। इस हड़ताल को पूरे देश का समर्थन मिला। आखिरकार का० कोल्ये पर मुअत्तली नोटिश वापस लेने और सभी मजदूरों को अतिरिक्त ४० रु० मंहगाई भत्ता देने को मालिक मजबूर हुए।

महाराष्ट्र के २ लाख पावरलूम मजदूरों ने वेतन बृद्धि, ८ घण्टे की ड्यूटी लागू करने और बन्द कारखाने खोलने की मांग पर कई संग्राम किये। सी आई टी यू की पहल पर १९७२ में एक राज्यव्यापी कन्वेन्शन किया गया और एक्शन कमेटी का गठन किया गया। २३ नवम्बर १९७३ से राज्यव्यापी हड़ताल की गई जो ज्यादातर पावरलूम केन्द्रों में कई दिनों तक चली। आखिरकार मालिकों को बाध्य होकर वेतन वृद्धि स्वीकारनी पड़ी और कई केन्द्रों में आठ घण्टे की ड्यूटी लागू की गयी। इस हड़ताल का एक खास पहलू यह था कि यद्यपि सभी हिस्से के मजदूरों द्वारा एकजुट होकर यह संग्राम किया गया, लेकिन इसका नेतृत्व भी सी आई टी यू ने किया।

राजस्थान

एरनाकुलम सम्मेलन के बाद राजस्थान में सी आई टी यू की उल्लेखनीय अग्रगति हुई है। यहां तक बुर्जुआ अखबारों ने भी यह स्वीकार किया है कि

१९७३ के बाद वाले ६ महीने में हमारे नेतृत्व में कई हड़तालें हुईं। इनमें प्रमुख है व्यापक टेक्सटाइल और कोटा के मल्टी के मजदूरों के संग्राम। लेकिन सी आई टी यू द्वारा छेड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण अभियान और संग्राम था राज्य के सरकारी मर्मचारियों के समर्थन में किया गया एकजुटता संग्राम। यह सबसे तीखा और लम्बा संग्राम था। एक महीने से ज्यादा समय तक इसने सम्पूर्ण प्रशासन को ठप्प कर दिया। हड़ताल १५ अगस्त १९७३ को शुरू हुई। बर्बर दमन सामूहिक गिरफ्तारी और गोली वर्षा के मध्य से मजदूरों को गुजरना पड़ा तथा पुलिस और गुण्डों ने कर्मचारियों के घरों पर हमले किये। यहां तक कि जिन्होंने हड़तालियों के प्रति एकजुटता जाहिर की, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। राज्य सी आई टी यू के अध्यक्ष मोहन पुनमिया और महासचिव दुर्गा दास शिराली को भी हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किया गया। सी आई टी यू ने ए आई टी यू सी एच एम पी तथा दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ एकजुट होकर २४ जुलाई १९७३ को राज्य कर्मचारियों के समर्थन में बंद आयोजित किया। इससे पहले १७ जुलाई १९७३ को राज्य बिजली बोर्ड के एक ड्राइवर को पुलिस की गोली वर्षा में हत्या के विरोध में एकजुट जयपुर बन्द किया गया। इस बन्द का आह्वान ट्रेड यूनियनों की कोआर्डिनेशन कमेटी की ओर से किया गया था।

१४ अगस्त १९७४ को १४४ धारा लागू करने के खिलाफ एक जन सत्याग्रह चलाने का आह्वान सी आई टी यू, ए आई टी यू सी और एच एम पी ने संयुक्त रूप से किया। सी आई टी यू, एच एम पी तथा अन्यों के नेतृत्व में १५०० स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी। राजस्थान के दूसरे भागों में भी सत्याग्रहियों के जत्थों ने दफा १४४ का उल्लंघन किया।

१४ फरवरी १९७४ को पूरे राज्य के पंद्रह हजार इंजीनियरिंग मजदूरों ने १०० रु० वेतन बढ़ाने, और अन्य मांगों के लिये हड़ताल की। एक ओर तो ए आई टी यू सी, आई एन टी यू सी, एच एम एस और अन्यों ने हड़ताल का विरोध करने के लिये हाथ मिलाया, दूसरी ओर मजदूरों का दमन करने के लिये तमाम कारखाने में राजस्थान आर्म्ड कन्सटेबुलरी के सिपाहियों को तैनात कर दिया गया। मजदूरों को आतंकित करने के लिये गुण्डों का भी इस्तेमाल किया गया। फिर भी, हड़ताल पूरी कामयाब रही। यह इसलिये मुमकिन हुआ क्योंकि फैक्टरी और स्थानीय स्तरों पर संयुक्त एक्शन कमेटी का गठन सी आई टी यू कर सकी, जिससे फूटपरस्तों को अपनी चाल चलने का कोई मौका नहीं मिला।

वेतन जाम के खिलाफ संग्राम में पहला खून बहाने का गौरव राजस्थान को है। भरतपुर स्थित सिमको कारखाने के मजदूर ११ अगस्त १९७४ को जब वेतन जाम अध्यादेश के जरिये लादे गये वेतन में कटौती का विरोध कर रहे थे, तब पुलिस ने गोली चलाई और ३ मजदूरों की बर्बर हत्या कर दी तथा कइयों को घायल किया। इस हत्याकांड के खिलाफ समूचे देश में स्वतः स्फूर्त प्रतिवाद किया गया। इसने और भी दृढ़ता और मजबूती के साथ वेतनजाम हमले के खिलाफ लड़ने के मजदूरों के निश्चय को शक्तिशाली बनाया।

वेतन-वृद्धि के लिये तथा ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों को कुचलने के खिलाफ कोटा एटामिक पावर प्रोजेक्ट तथा बेहतर तलब और बेहतर काम की हालतों के लिये सोप स्टोन के मजदूरों के संग्रामों को भी आस-पास के इलाकों के मजदूरों का समर्थन प्राप्त हुआ।

४ मार्च १९७४ को जे० के० सिन्थेटिक के प्रबन्धकों ने अपने भाड़े के गुण्डों के जरिये सी आई टी यू से संबद्ध जे० के० सिन्थेटिक मजदूर यूनियन के प्रमुख नेताओं पर जानलेवा हमले किये। सिर्फ मजदूरों की सतर्कता के कारण उनकी जानें बच गईं। लेकिन राजस्थान पुलिस ने उल्टे ५० यूनियन नेताओं को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया। प्रबंधकों ने भी इन्हीं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर इन मजदूर नेताओं की छंटाई की कोशिश की। सी आई टी यू को दबा देने की इस मिलीजुली साजिश के खिलाफ राज्य कमेटी की ओर से मजदूरों के बीच प्रचार चलाया गया।

आंध्र प्रदेश

बढ़ती कीमतों और भयावह कालाबाजारी के खिलाफ २४ अगस्त १९७३ को सफल आंध्र बंद मनाया गया। बंद का आह्वान सी आई टी यू, ए आइ टी यु सी, एच एम पी, की राज्य युनिटों बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन, आंध्र प्रदेश दुकान कर्मचारी फेडरेशन ने किया था और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी इसका समर्थन कर रही थी।

२ अगस्त को एच एम टी के ३ हजार मजदूरों ने उस वक्त स्वतः स्फूर्त हड़ताल कर दी जब प्रबंधकों ने बदले की भावना से यूनियन के तीन नेताओं को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने जनरल मैनेजर का घेराव किया और तब तक फैक्टरी में बैठे रहे जब तक कि जिला कलक्टर के हस्तक्षेप से समझौता न

हुआ । ३ अगस्त को तालाबन्दी खत्म कर दी गई ।

कोरोमडेल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मजदूर २० अगस्त १९७३ से लगातार हड़ताल पर चले गये । प्रबंधकों ने यहां सभी तरक्कियों पर रोक लगा दी थी और बेशुमार मुनाफे के बावजूद बोनस देने से वे इनकार कर रहे थे । इसीलिये यह हड़ताल हुई । प्रबंधकों ने मुख्य श्रम कमिश्नर की सलाह को भी ठुकरा दिया और समझौता वार्ता में शामिल नहीं हुये । मजदूरों को हटाने के लिये आंध्र सरकार ने इस अमरीकी सहयोग वाले प्रबंधकों का पूरा पक्ष लिया । फिर भी हड़ताल ३४ दिनों तक चलती रही ।

गैमोन (इंडिया) लिमिटेड के तमाम मजदूरों ने ६ अगस्त से हड़ताल की । यह कम्पनी विशाखापतनम में बन्दरगाह निर्माण कार्य की ठेकेदार है । मजदूरों की मांगें थीं : ६ बर्खास्त मजदूरों की फिर से बहाली और १९७१ के समझौते को लागू करना ।

पश्चिमी गोदावरी जिले की ६० चावल मिलों के २ हजार मजदूरों ने ४० दिन तक हड़ताल चला कर अपनी तलब में औसतन ३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हासिल की । राज्य सरकार ने अकीभीडु तालुका के ३०० मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मजदूरों की संगठित शक्ति के सामने अंत में उनकी अकड़ ढीली पड़ गयी । खम्माम जिले के लकड़हारों, वारंगल और गुंटूर के रिक्शा-चालकों, कृष्णा जिले की खांडसारी सुगर मिल के मजदूरों ने भी सी आई टी यू के नेतृत्व में सफल हड़तालें कीं । इसके अलावा वेतन वृद्धि और काम की बेहतर हालतों के लिये निम्नलिखित संस्थाओं में सी आई टी यू के नेतृत्व में सफल संग्राम किये गये : इ सी आई ई, हिंदुस्तान शिपयार्ड के कैंटीन मजदूर, विशाखापतनम के कमल इंडस्ट्रीज, विजयवाड़ा के अलमुनियम मजदूर, करनूल के लक्ष्मी निवास होटल के मजदुर, नेल्लोर के इनामेल मजदूर, वारंगल के बीड़ी मजदूर, विजय-वाड़ा के मुठा मजदूर ।

आंध्र प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में २४० गांव के खेत मजदूरों ने हड़ताल की । उन पर जमींदारों के भाड़े के गुण्डों और पुलिस ने हमले किये । इतना होने पर भी अपनी मजूरी बढ़ाने में वे सफल हुये ।

कर्नाटक

चिकमागलूर, हसन और दक्षिणी कनारा जिले के ४० हजार बगीचा

मजदूर २७ दिसम्बर १९७३ से हड़ताल पर चले गये। वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि, २० प्रतिशत बोनस, बगीचा मजदूर एक्ट लागू करने की मांगों पर उन्होंने यह हड़ताल की। सी आई टी यू, एच एम एस और आई एन टी यू सी के संयुक्त आह्वान पर यह हड़ताल हुई। लेकिन, वास्तव में वेतनजाम को मानते हुए ए आई टी यू सी के नेताओं ने प्रबन्धकों के साथ एक विश्वासघातक समझौता कर लिया। मगर मजदूरों ने इस समझौते को ठुकरा दिया और सफलता के साथ हड़ताल जारी रखी। सिर्फ तभी हड़ताल खतम की गई जब कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया और इस बात पर राजी हुये कि ए आई टी यू सी के विश्वासघातक समझौते को ठुकरा कर हड़ताल से संबंधित तमाम मुद्दों पर नये सिरे से बातचीत शुरू की जायेगी।

पिछले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में जिन हड़तालों में सबसे तीखी लड़ाई डांडेली स्थित वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के साढ़े तीन हजार मजदूरों की हड़ताल उनमें एक है। अधिक मंहगाई भत्ता, सी आई टी यू यूनियन को मान्यता, ६ सौ कैजुअल और १२०० ठीका मजदूरों को नियमित करने की मांगों तथा ठीका प्रथा खत्म करने की मांगों पर यह हड़ताल हुई थी। इस इलाके के विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों ने इस हड़ताल के प्रति एकजुटता ज़ाहिर की जो डांडेली बंद के माध्यम से अपने शिखर पर पहुंच गया। तमाम जनसंगठनों जिनमें आई एन टी यू सी का एक हिस्सा भी शामिल था, की संयुक्त अपील पर यह बंद हुआ।

मूल्य वृद्धि के खिलाफ २९ अगस्त १९७३ को सम्पूर्ण दक्षिणी कनारा ज़िले में बंद पालन किया गया। सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, पी एंड टी यूनियन, मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड, जीवन बीमा तथा ए आई बी ए के आह्वान पर यह बंद हुआ। बन्द के दिन पूरा यातायात ठप्प था। खपड़ा, काजू, कॉफी तथा बीड़ी उद्योग और इंजीनियरिंग इकाइयां सम्पूर्ण रूप से बंद रहीं। इसीदिन चिकमागेलोर, हसन तथा दक्षिणी कनारा जिले के बगीचा मजदूरों ने भी इसी मांग पर हड़ताल की।

गोवा

गोवा के कोका-कोला मजदूरों के लम्बे संग्राम ने विभिन्न विचारों की ट्रेड यूनियनों को एकजुटता संग्राम के मैदान में ला खींचा। यह संग्राम २३

नवम्बर १९७३ से शुरू हुआ। सी आई टी यू की आल गोवा जनरल इम्पलाइज यूनियन में जैसे ही मजदूर शामिल हुये, ३ अगुआ मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें चार्जशीट भी न दी गई। इसके बाद ही मजदूरों से बदला लेने की गरज से प्रबंधकों ने २३ ता० से एक तरफा तौर पर तालाबन्दी की घोषणा कर दी। प्रबन्धकों ने समझौता वार्त्ता में बैठने से भी इन्कार कर दिया। १८ जनवरी को फैक्टरी गेट पर उपस्थित मजदूरों पर गुण्डों और संयुक्त गोअन पार्टी के दो विधायकों द्वारा गोली चलायी गयी, जिससे ११ मजदूर घायल हो गये। इस हमले का विरोध तमाम ट्रेड यूनियनों ने किया और कोका-कोला मजदूरों के समर्थन में एकजुटता संग्राम चलाने के लिये एक एक्शन कमेटी का गठन किया। इसी एक्शन कमेटी की ओर से १८ फरवरी १९७४ को सफल गोवा बंद आयोजित किया गया। लेकिन, मजदूरों को फिर से काम पर लेने पर, प्रबंधक राजी न हुये और मामले को ट्राइबनल में भेज दिया गया।

खान और इंजीनियरिंग मजदूरों ने पूरे राज्य में हड़तालों का तांता लगा दिया। एक इटालियन कंपनी के मजदूरों ने अपने छंटाईशुदा साथियों की फिर से बहाली और वेतन-वृद्धि की मांग पर हड़ताल की। दक्षिणी गोवा के अग्रवाल माइन्स, डेम्पो माइनिंग कारपोरेशन तथा बिचोलिम के बन्दोदकर माइंस के मजदूरों ने भी अपनी मांगों के लिये लम्बा संग्राम चलाया। एक सफल संग्राम के बाद जानी शिपिंग और डेबोलिन के जहाज निर्माण कारखाने के इंजीनियरिंग मजदूरों ने प्रति महीने ५० से लेकर ७५ रु० की वेतन बढ़ोत्तरी हासिल की। चौगुले के खान और इंजीनियरिंग मजदूर और अन्य कंपनियों के मजदूरों द्वारा बोनस के लिये और छंटाई के खिलाफ कई संग्राम किये गये।

१९७४ में, सी आई टी यू और एच एम एस के मिले-जुले आह्वान पर मारमा गोवा के गोदी मजदूरों ने ४ दिनों की हड़ताल की। वे पोर्ट ट्रस्ट से आई एन टी यू सी के प्रतिनिधियों को हटाने की मांग कर रहे थे। इस तरह आई एन टी यू सी का नेतृत्व विछिन्न हो गया और मजदूरों के हितों के खिलाफ उसकी गद्दारी भरी भूमिका बेपर्द हो गई।

मजदूरों के एकजुट संग्राम संगठित करने में सी आई टी यू की यूनियनों ने नेतृत्वकारी भूमिका निभायी और मजदूरों के हितों के लिये अविचल संग्राम किया। उसके इन कामों तथा दूसरी ओर आई एन टी यू सी और अन्य सुधारवादी यूनियनों की विश्वासघाती भूमिका ने गोवा में सी आई टी यू को एक नयी चुनौती दी है तथा उसके सामने नयी सम्भावनाओं का द्वार खोल दिया है।

बिहार

७ जून १९७३ को राज्य की बामपंथी पार्टियों के आह्वान पर मुकम्मिल बिहार बन्द मनाया गया। यह बंद का० सूरज नारायण सिंह की हत्या तथा मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया गया। का० सूरज नारायण सिंह की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वे अनशन कर रहे थे। बंद पूरा सफल रहा।

१९७४ में भारत की कोलियरी मजदूर सभा के झंडे के नीचे ६ कोयला-खानों के मजदूरों ने सफल हड़ताल की और बरूरा के कस्टोडियन आफिस के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जब वे लौट रहे थे तो सेन्ट्रल केन्दुआडिह कोलियरी स्थित कोलियरी मजदूर सभा के आफिस के अन्दर पुलिस उन पर टूट पड़ी और भयंकर लाठी चार्ज किया। बाद में पुलिस ने १५० चक्र गोलियां चलायी जिसमें एक मजदूर घायल हो गया, १९ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया तथा बस्तियों को लूटा गया।

नयी पारी चालू करने के खिलाफ पावर प्लांट के मजदूरों ने ३ जून १९७३ से ४ दिन की सम्पूर्ण हड़ताल की। इस नयी पारी के अनुसार मजदूरों को हफ्ते में एक बार डबल पारी काम करना होता। अन्त में, ६ जून को प्रबंधक झुके और नयी पारी खत्म कर दी गयी।

आदित्यपुर में सी आई टी यू की यूनियन के नेतृत्व में जेनिथ ड्राफ्ट कंपनी के मजदूरों द्वारा ६३ दिन लम्बी हड़ताल की गई। संग्राम के जरिये, बिहार इनसेक्टीसाइड पायनियर इन्जीनियरिंग माइनिंग इक्विपमैंट मिनरल इंडिया आदि के मजदूर अपनी कुछ माँगें हासिल करने में सफल हुए।

जमशेदपुर के इंडियन ट्यूब कारखाने में मजदूरों के संग्राम के सामने बरखास्तगी के आदेश रद्द करने पड़े। वेतन वृद्धि के लिये भी मजदूरों ने आंदोलन चलाया। ३ मजदूरों की बरखास्तगी और ४ की मुअत्तली के खिलाफ एफ० एम० मिल्स के मजदूरों ने ४४ दिनों तक हड़ताल की। अन्त में मालिक को झुकना पड़ा और २६ अक्टूबर १९७३ को यूनियन के साथ मांगों पर समझौता हुआ। मार्च १९७४ में मालिकों द्वारा की गई तालाबन्दी के खिलाफ मजदूरों ने फिर संग्राम किया। २२ नवम्बर १९७३ को वेतन वृद्धि की मांग पर टेल्को के मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल की। सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, एच एम एस तथा आई एन टी यू सी के एक हिस्से के आह्वान पर यह हड़ताल हुई। हड़ताल के बाद मजदूरों की विशाल सभा को अन्यों के

साथ सी आई टी यू के उपाध्यक्ष का० महम्मद इस्माइल ने भी सम्बोधित किया। आई एन टी यू सी के मठाधीशों की गद्दारी के खिलाफ टिस्को कर्मचारी के समिति ने लड़ाई की अक्टूबर १९७३ में मजदूरों की एक विशाल सभा में सी आई टी यू के अध्यक्ष का० बी० टी० रणदिवे ने भाषण दिया।

कोयलाखानों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी धनबाद और झरिया अंचल में ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ गुण्डागर्दी और आतंक जारी है। १५ नवम्बर '७३ को सिजिरा में सिक्यूरिटी फोर्स और सरकारी संस्थानों द्वारा भर्ती किये गये गुण्डों ने उस वक्त गोली चलाकर १ महिला समेत ६ मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया जब मजदूर भारत कोकिंग कोल कम्पनी में गुण्डों के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कई मजदूर बुरी तरह घायल भी हो गये। २० नवम्बर १९७३ को सी आई टी यू, ए आई टी यू सी और एच एम एस के संयुक्त आह्वान पर धनवाद-झरिया अंचल में एक दिन की प्रतिवाद-हड़ताल की गई। कोयला मजदूरों के संग्रामों के दौरान विभिन्न मौकों पर सरकार ने सी आई टी यू के जनरल कौंसिल के सदस्य का० ए० के० राय तथा बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के और भी अनेक अगुआ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाया। लेकिन इतने दमन के के बावजूद, कोयलाखान इलाकों में सी आई टी यू का असर बढ़ा है।

इसके अलावा, रिफ्रैक्टरी मजदूर, रांची के बाक्साइट मजदूर, बेतिया के पथ परिवहन मजदूरों ने भी अपनी मांगें हासिल करने के लिये संग्राम किये।

मजदूर संघर्षों के दौरान राज्य कमेटी के महासचिव का० चण्डी प्रसाद को कई बार गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय झंडे को अपमान के मनगढ़ंत अरोप में उन्हें नजरबन्द भी किया गया।

जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा बिहार विधान सभा भंग करने तमाम बंदियों की रिहाई, तथा चुनाव सुधार के लिये बड़ा भारी संग्राम चलाती आ रही है। इस संग्राम में मजदूर वर्ग ट्रेड यूनियन आंदोलन की कमजोरी के कारण अपना उचित पार्ट नहीं अदा कर सका। चूंकि राज्य में सी आई टी यू एक छोटी शक्ति है, लिहाजा इन मांगों के समर्थन में वह मजदूर वर्ग को गोलबंद नहीं कर सका।

उत्तर प्रदेश

कानपुर में जे० के० जूट मिल की लम्बी हड़ताल के बाद जो सबसे लम्बा और तीखा संग्राम हुआ वह था विदेशी इजारेदार कंपनी आई सी आई के

मालिकाधीन इन्डियन एक्सप्लोसिव के मजदूरों का संग्राम। दंभी प्रबन्धकों ने पहले के समझौते को तोड़ा और मजदूरों के कंधों पर काम अतिरिक्त बोझ लादने की कोशिश की। अप्रेल १९७३ से मजदूरों ने इसका प्रतिरोध किया। तालाबंदी कर दी गई। यूनियन के महासचिव समेत ७० मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा सी आर पी को मजदूरों के पीछे छुट्टा छोड़ दिया गया। ढाई महीने बाद मामले को पंच के पास भेजा गया। अन्त में, १८ जुलाई १९७३ को आई ई एल इम्प्लाइज यूनियन के साथ मुख्य मांगों पर समझौता करने पर प्रबन्धक मजबूर हुये। हड़ताल १२३ दिनों तक चली।

सी आई टी यू के आह्वान पर, गाजियाबाद के १२ इन्जीनियरिंग इकाइयों के ५००० मजदूरों ने ७० रु० अन्तरिम राहत और मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ जोड़ने की मांग पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। सी आई टी यू के नेताओं की गिरफ्तारी और ए आई टी यू सी के विरोध के बावजूद हड़ताल कामयाब रही।

आसाम

जरूरत के मुताबिक न्यूनतम तलब, मूल्य वृद्धि की पूरी क्षतिपूर्ति २० प्रतिशत घरभाड़ा आदि मांगों समेत २० सूत्री मांग पत्र पर ८५ हजार राज्य सरकारी कर्मचारियों ने लगातार हड़ताल की, जो १८ दिसम्बर १९७३ से शुरू हुई। तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने कर्मचारियों का जोरदार समर्थन किया। फलतः हड़ताल लम्बी चली। अन्त में सरकार को मजबूर होकर सुविधायें देनी पड़ी।

ओड़िसा

बरसुआ लोहा अयस्क खान में यूनियन की कार्यकारिणी के २६ सदस्यों को बगैर समझे बूझे बर्खास्त कर दिया गया। इसके खिलाफ मजदूरों को लंबी लड़ाई करनी पड़ी। यद्यपि जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि यूनियन की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, फिर भी उसे मान्यता नहीं दी गई। एक लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद प्रबन्धकों को रोका गया और कोर्ट के आदेश से तमाम नेताओं की फिर से बहाली हुई। छँटाई के खिलाफ और ट्राइबूनल की सिफा-

रिशों को लागू करने तथा अन्य मांगों के लिये बालीमेला परियोजना के मजदूर कर्मचारी संयुक्त कौंसिल का गठन किया और एकजुट होकर संग्राम चलाया।

रौरकेला स्टील प्लांट के ढीका मजदूरों, फेरो-क्रोम खान मजदूरों, परिवहन मजदूरों तथा पुरी म्यूनिसिपल के मजदूरों ने भी संग्राम कर कुछ मांगें हासिल की।

मध्य प्रदेश

भिलाई में हिन्स्तान स्टील इम्पलाइज यूनियन ने १९७२-७३ के लिये २० प्रतिशत बोनस की मांग पर आन्दोलन चलाने में पहल की। ट्रेड यूनियनों ने एकबद्ध होकर सफलता पूर्वक बोनस का बायकाट किया और हड़ताल की नोटिश दी। लेकिन आई एन टी यू सी के नेताओं ने दगा किया तथा एक्सग्रासिया के तौर पर १०० रु० और विधिबद्ध न्यूनतम बोनस दिया गया। एक प्रचार अभियान के जरिये सी आई टी यू ने इस दगाबाजी की व्याख्या की।

ए आई एन टी यू सी की गद्दारी के बावजूद विश्रामपुर कोलियरी में सी आई टी यू के नेतृत्व में १५ नवम्बर १९७३ को एक दिन की हड़ताल हुई। सुराकछार कोलियरी के मजदूरों ने अपने यूनियन नेताओं की बरखास्तगी के खिलाफ लम्बा संग्राम चलाया।

नागदा के ग्रेसिम मजदूर, इन्दौर के टेक्सटाइल मजदूर, उज्जैन के सिन्थेटिक मजदूर, भोपाल तथा दामोह के बीड़ी मजदूर, मंदसौर के स्लेट पेन्सिल मजदूर तथा ग्वालियर के छाता मजदूरों द्वारा भी सी आई टी यू के नेतृत्व में संग्राम किये गये।

दिल्ली संभाग

जब हम एरनाकुलम में सम्मेलन कर रहे थे, उसी समय २७००० टेक्सटाइल मजदूर मुकम्मिल हड़ताल चला रहे थे। हड़ताल की मांगें थी : वेतन में बढ़ोत्तरी और अन्तरिम राहत। हड़ताल चलाने के लिये सी आई टी यू, एच एम पी तथा आइ एन टी यू सी के एक हिस्से को लेकर संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन स्थानीय ए आई टी यू सी के नेताओं ने इसका विरोध किया। २० रु० प्रति महीने की अन्तरिम राहत और प्रति मजदूर २०० रु० अग्रिम प्राप्त करने के बाद ही ५ मई १९७३ को हड़ताल खत्म हुई। महंगाई भत्ते के पुन–

रीक्षण के सवाल को पंच के अधीन सौंप दिया गया। सी अ ई टी यू ने बड़े ही असरदार तरीके से मामले को पेश किया जिसे पंच ने भी नोट किया। यहां तककि पंच की सिफारिशों को लागू कराने के लिये भी मजदूरों को संग्राम करना पड़ा। दो दशकों के बाद टेक्सटाइल में यह पहली हड़ताल थी न सिर्फ टेक्सटाइल मजदूरों पर बल्कि आस पास के अन्य मजदूरों पर भी इस हड़ताल का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा।

६ जलाई १९७३ को गुडइयर के हड़ताली मजदूरों के प्रति एकता का इजहार कर रहे प्रदर्शनरत मजदूरों पर हरयाणा पुलिस ने गोली दागी, जिससे एक मजदूर की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये। ये मजदूर गिडोर फैक्टरी के थे, जिन्होंने हाल ही में ए आई टी यू सी को ठुकरा कर सी आई टी यू की यूनियन में शामिल हुए थे। पुलिस ने मजदूरों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े तथा दूसरे दिन यूनियन आफिस को तोड़ फोड़ दिया। १२ नवम्बर १९७३ को फरीदाबाद के उषा स्पीनिंग मिल्स के १६०० मजदूरों ने हड़ताल की। वे ५० रु० अन्तरिम राहत, बोनस और छंटाईशुदा मजदूरों की फिर से बहाली की मांग कर रहे थे। १६ मजदूरों की गिरफ्तारी और ए आई टी यू सी के नेताओं की गुण्डागर्दी के बावजूद हड़ताल कई दिनों तक चली और मजदूरों ने कुछ मांगें हासिल की।

एक पिट्ठू युनियन थोपने की प्रबंधकों की नीति तथा सी आई टी यू यूनियन के नेताओं के खिलाफ गूण्डागर्दी के विरुद्ध "स्टेटसमैन" के दिल्ली संस्करण के मजदूरों ने भी एक लम्बा संग्राम किया। गुण्डों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुये सितम्बर १९७३ में मजदूरों को हड़ताल तक करनी पड़ी। चार्ज-शीट जारी करने के प्रबन्धकों के कदम को नाकाम कर दिया। लेकिन बाद में प्रबन्धक ने सी आई टी यू की राज्य कमेटी के सचिव का० नागराजन सहित बड़ी संख्या में मजदूरों को मुअत्तल कर दिया। फूट डालने की मैनेजमेंट की कोशिशों के बावजुद, संग्राम अब भी जारी है। इस संग्राम में कलकत्ता युनियन ने दिल्ली के कामरेडों के साथ एकजुटता नहीं दिखाई जिसने सिर्फ मालिकों को ही इस तरह बदला लेने का कदम उठाने को उत्साहित किया।

६ नवम्बर १९७३ को सफल बन्द दिल्ली के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण घटना है। विधिबद्ध राशनिंग, जरूरत के मुताबिक तलब, पुलिस जुल्म बन्द करने तथा जमाखोरों के खिलाफ कदम की मांग पर सी आई टी यू, ए आई टी यू सी, यू टी यू सी और एच एम पी के संयुक्त आह्वान पर तथा

वामपंथी पार्टियों और जनसंगठनों के समर्थन से यह बन्द आयोजित किया गया। यह पहला मौका था कि राजधानी में इतने विराट आकार की कार्रवाई की गई जिससे समूची राजधानी ठप्प हो गयी।

इसके अलावा, इंजीनियरिंग होटल, निर्माण-कार्य, एप्लाइड इकोमोमिक्स की राष्ट्रीय कौंसिल, मैकमेल बेरी एंड कं० के मजदूर कर्मचारियों ने भी सी आई टी यू के नेतृत्व में संग्राम किये।

कामरेडों,

इस सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण तथा साथ ही साथ महासचिव की रिपोर्ट में, इन संग्रामों की पृष्ठभूमि पर और भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अतः इसे सिर्फ इन संग्रामों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने के लिये पेश किया जा रहा है।

यह देखा जाता है कि जहां कहीं भी सी आई टी यू और उसके मित्र काम कर रहे हैं, वहां मजदूर वर्ग के संगठित आन्दोलन और संग्राम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तककि जहां हम कमजोर हैं वहां भी मदद और मार्ग दर्शन के लिये मजदूर हमारी ओर देखते हैं। कुछ स्थानों में, अपने नेताओं की गद्दारी को देखकर मजदूर हमारी तरफ चले आये हैं।

मजदूरों के सभी हिस्सों में एकता का आग्रह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जहां कहीं भी मजदूरों के तमाम हिस्सों को गोलबन्द करने में हम समर्थ हुये हैं, वहां सुधारवादी और संशोधनवादी नेताओं के लिये अपने अनुगामियों को संग्राम से दूर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है तथा वे भी संग्राम में शामिल होने के लिये बाध्य कर दिये जाते हैं। अगर मजदूरों की एकता को पूरी तरह बरकरार रखा जाता है तो ये मौकापरस्त नेतृत्व मजदूरों के साथ दगाबाजी करने में नाकाबिल हो जाते हैं यद्यपि यह परिस्थिति उनके लिये असहनीय होती है। लेकिन ज्यों ही उन्हें ऐसा करने का पहला मौका मिलता है, वे मैनेजमेंट के सामने घुटने टेकने की कोशिश करते हैं।

ए आई टी यू सी और आई एन टी यू सी के नेता ट्रेड यूनियन जनवाद को बेशर्मी से तोड़ने वालों के रूप में सबसे आगे आये हैं जिन्होंने मजदूरों की राय लिये बगैर कई समझौतों पर दस्तखत किये हैं। ए आई टी यू सी और आई एन टी यू सी के बार-बार के फूटपरस्त करनामों और यथा सम्भव व्यापक एकता कायम करने की सी आई टी यू की कोशिशें मजदूरों के सामने ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होती जा रही हैं और वे सी आई टी यू को मजदूर वर्ग के

तमाम हिस्सों को एक सूत्र में पिरोनेवाले के रूप में देखने लगे हैं ।

जो एकजुट संग्राम फैक्टरी या स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे थे, वे अब क्रमशः आंचलिक या राज्यव्यापी संग्रामों का रूप धारण कर रहे हैं और यहाँ तकि विभिन्न समय में वे देशव्यापी संग्राम का रूप भी ले लेते हैं। संग्रामों को और भी शक्तिशाली बनाने में सी आई टी यू को उनकी चेतना की इस ऊँचाई का पूरी तरह इस्तेमाल करना होगा ।

मजदूर वर्ग के एक हिस्से के समर्थन में दूसरे हिस्से के एकजुटता संग्राम लगातार बढ़ रहे हैं । मजदूर वर्ग के तमाम हिस्सों के खिलाफ सरकार के हमले इस तरह मजदूरों को और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब ला रहे हैं । वेतन जाम आंदोलन और रेल मजदूरों के प्रति एकजुटता संग्राम के अनुभव से यह साफ जाहिर है कि मजदूर वर्ग के विभिन्न हिस्सों और वेतन भोगी कर्मचारियों के बीच कांग्रेस सरकार की नीतियों के लिखाफ एकजुट संग्राम की नयी चेतना विकसित हो रही है ।

ऊँची कीमतें, खाद्य का अभाव, बेरोजगारी तथा ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों में कटौती के खिलाफ एकजुट ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने दृढ़ता के साथ संग्राम चलाया । इसने शहरी और देहाती जनता के पिछड़े हिस्सों को भी संग्राम में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया । बहुत सी जगहों में, विकल्प नीतियों के लिये संग्राम में पहलकदमी करने में ट्रेड यूनियनें समर्थ रही हैं ।

पुलिस जुल्म और गुण्डागर्दी के खिलाफ लड़ाई में मजदूर वर्ग ने बेमिसाल दिलेरी दिखाई है । दमन यंत्रों की सहायता से ट्रेड यूनियन और जनवादी आंदोलनों को कुचलने की तमाम कोशिशें बुरी तरह असफल हुई हैं । ऐसे कदमों ने और भी दृढ़ता के साथ अपना संग्राम चलाने के मजदूरों के इरादे को बुलन्द किया है ।

जबकि सरकारी नीतियां मेहनतकशों के तमाम हिस्सों पर कहर ढा रही हैं, इन नीतियों के खिलाफ आम संघर्ष हर गुजरे दिन के साथ ही और भी व्यापक हो रहा है । इन संग्रामों में समन्वय और आम सवालों पर मजदूर वर्ग के तमाम हिस्सों को एकजुट करने में सी आई टी यू को अहम भूमिका निभानी है, ताकि वह संग्राम देश के आम जनवादी के साथ एकाकार हो जाय ।

सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिये एम० के० पंधे द्वारा १७२, लेनिन शरणी, कलकत्ता-१३ से प्रकाशित और गल्प भारती प्रेस, १६/१७, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता-१२ से मुद्रित